वर्ष 12 • अंक 289 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

बुधवार 22 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

अजय त्यागी ▶▶ पृष्ठ 3

पीएमएस के लिए अग्रिम शुल्क पर सेबी की कैंची

पीयूष गोयल ▶▶ पृष्ठ 14

व्यापार संबंधों में बरती जाएगी निष्पक्षता

डॉलर रु. 71.20 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 79.10 ▲ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 39854 ▼ 97 रुपये | सेंसेक्स 41323.80 ▼ 205.10 | निफ्टी 12169.80 ▼ 54.70 | निफ्टी फ्यूचर्स 12203.10 ▲ 33.30 | ब्रेंट क्रूड 63.60 डॉलर ▼ 1.40 डॉलर

एक नज़र

5,100 करोड़ रुपये की सैन्य सामान खरीद को मंजूरी

रक्षा मंत्रालय ने 5,100 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसकी खरीद स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए छह पनडुब्बियों के निर्माण के लिए महत्त्वाकांक्षी रणनीतिक साझेदारी मॉडल पर आगे बढ़ने को भी हरी झंडी दे दी। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे।

बैंक धोखाधड़ी में फ्रॉस्ट इंटरनैशनल पर मामला दर्ज

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 14 बैंकों के समूह के साथ 3,592 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के सिलसिले में मुंबई की कंपनी फ्रॉस्ट इंटरनैशनल, उसके निदेशकों उदय देसाई और सुजय देसाई के अलावा 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई बैंक ऑफ इंडिया के कानपुर जोन कार्यालय की शिकायत पर की गई है। बैंक का आरोप है कि निदेशकों का कोई वास्तविक कारोबार नहीं है फिर भी उन्होंने कर्ज लेने के लिए व्यापारिक गतिविधियों की आड़ ली। बैंक का आरोप है कि निदेशकों ने बैंक ऑफ इंडिया के अगुआई वाले ऋणदाता बैंकों के समूह को भुगतान करने में चूक की है। पृष्ठ 4

प्याज निर्यात से पाबंदी हटाने का विचार

नई फसल की आवक शुरू होने से घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें धीरे-धीरे कम हो रही है। ऐसे में सरकार प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाने पर विचार कर रही है। प्याज के दाम अभी 60 से 70 रुपये किलो के आसपास है जो पिछले महीने 160 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। ताजे प्याज की आवक जनवरी से मई तक होती है। सितंबर 2019 में सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी।

मोदी करेंगे 32वीं प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सक्रिय प्रशासन और विभिन्न परियोजनाओं के सामयिक क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए 32वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक बहुउद्देश्ईय मंच है। आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रगति के पिछले संवादों के दौरान प्रधानमंत्री ने 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की थी।

आज का सवाल

क्या दूरसंचार कंपनियों को मिलनी चाहिए भुगतान से राहत

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या संपत्तियों की बिक्री से पूरा होगा विनिवेश का लक्ष्य?	
हां	70.00%
नहीं	30.00%

भुगतान पर एकमत नहीं फर्में

सर्वोच्च न्यायालय ने अगले हफ्ते सुनवाई के लिए स्वीकार की नई याचिका

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 21 जनवरी

अग्रणी दूरसंचार कंपनियां अभी तय नहीं कर पाई हैं कि 24 जनवरी की समयसीमा के अंदर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का बकाया भुगतान किया जाए या नहीं। इसकी वजह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय तीन दूरसंचार कंपनियों की संशोधन याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई को राजी हो गया है।

भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा समूह ने अदालत में सोमवार को याचिका दायर कर 1.47 लाख करोड़ रुपये के एजीआर बकाये के भुगतान की 90 दिन की समयसीमा में बदलाव की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने भुगतान के समय और शर्तों को लेकर दूरसंचार विभाग से बातचीत करने की अनुमति भी मांगी थी। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा, 'मुझे लगता है कि अधिकतर दूरसंचार कंपनियां भुगतान करने से पहले नई याचिका पर सुनवाई होने तक इंतजार करना चाहेंगी।' कुछ ऐसी ही राय वोडाफोन आइडिया का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील शैली भसीन ने भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई एजीआर बकाये का भुगतान नहीं कर रही हैं और उन्होंने अदालत से दूरसंचार विभाग के साथ भुगतान योजना तय करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि भारती एयरटेल अग्रिम राशि का भुगतान करेगी या नहीं। कंपनी ने इस मसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

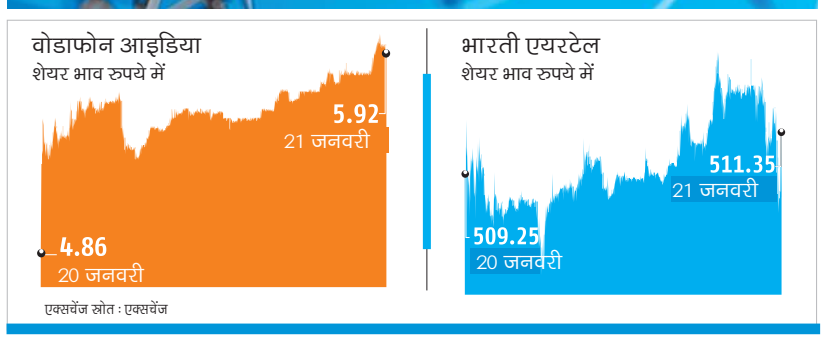

इस बीच दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा मौजूदा 49 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी। कंपनी को रिजर्व बैंक से भी 74 फीसदी तक एफडीआई की अनुमति मिल चुकी है।

नई याचिका में जियो अन्य दूरसंचार कंपनियों के साथ नहीं थी और उम्मीद की जा रही है कि वह तय समयसीमा में भुगतान कर देगी। जियो ने पिछली तिमाही के नतीजों के समय 2010-11 से 2018-19 की अवधि के लिए 177 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की देनदारी का अनुमान लगाने की घोषणा की थी। (शेष पृष्ठ 3 पर)

एफएमसीजी उद्योग के पटरी पर लौटने की आस

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 21 जनवरी

सितंबर, 2018 से लगातार पांच तिमाहियों तक गिरावट के बाद आखिरकार एफएमसीजी उद्योग के पटरी पर लौटने की उम्मीद दिखने लगी है। बाजार विश्लेषक नीलसन और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक इस साल एफएमसीजी क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और जनवरी-मार्च तिमाही में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी।

नीलसन के अनुमानों के मुताबिक भारत का 4 लाख करोड़ रुपये का एफएमसीजी बाजार 2020 में 10 फीसदी की वृद्धि हासिल कर सकता है। मौजूदा तिमाही में इसके 8-9 फीसदी की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। पिछली तिमाही में उसकी वृद्धि दर 6.6 फीसदी रही थी जो सात साल में सबसे कम है। यह वित्त वर्ष 2018-19 की दिसंबर तिमाही में 15.7 फीसदी थी।

नीलसन के दक्षिण एशिया क्षेत्र के अध्यक्ष प्रसून बसु के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही से शुरू हुआ गिरावट का दौर 2019 में थम सकता है। उन्होंने कहा, 'पिछला साल एफएमसीजी उद्योग के लिए बहुत मुश्किल रहा था जिसमें चार अंक की गिरावट आई थी। लेकिन इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में इसके पटरी पर लौटने की उम्मीद है। वृहद आर्थिक और विनिर्माण से जुड़ने कारकों के साथ-साथ कुछ छोटी कंपनियों के एकीकरण की इस सुस्ती में अहम भूमिका रही है।' क्रिसिल ने मार्च-अप्रैल तिमाही में वृद्धि के पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई है। रेटिंग एजेंसी ने 57 एफएमसीजी कंपनियों का विश्लेषण किया जो बाजार में सक्रिय कंपनियों की लगभग आधी संख्या है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के बाजार के 2020-21 में 11-12 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इससे अगले वित्त वर्ष में एफएमसीजी बाजार 10-11 फीसदी की दर से बढ़ सकता है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

- नीलसन का जनवरी-मार्च तिमाही में 8-9 फीसदी वृद्धि का अनुमान
- 2020 में 10 फीसदी की दर से बढ़ सकता है एफएमसीजी बाजार
- क्रिसिल को ग्रामीण बाजार में सुधार से 2020-21 में 10-11 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद
- डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की वृद्धि 11-12 फीसदी रहने का अनुमान

दिल्ली : उद्योग को भी बिजली बिल में राहत का वादा

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जनवरी

- दिल्ली के ऊर्जा व उद्योग मंत्री ने उद्यमियों को दिया राहत भरोसा
- सर्कल दरें तर्कसंगत बनाने और उद्योग को फ्री होल्ड का वादा

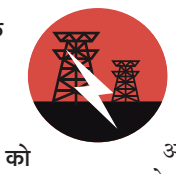

दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर राहत दी गई है लेकिन उद्योग पर इसका बोझ बढ़ा है। ऐसे में उद्यमी भी बिजली बिलों में राहत देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उद्यमियों की इस मांग पर आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के ऊर्जा व उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने चुनाव जीतने पर राहत देने का वादा किया है।

आप व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक बृजेश गोयल ने बताया कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने सोमवार रात बिजली व उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन मुलाकात की। जिसमें उद्यमियों ने जैन से घरेलू उपभोक्ताओं की तर्ज पर उद्योग को भी बिजली बिल में राहत की मांग की। उद्यमियों ने इस बैठक में सर्कल दरों में विसंगतियों के मुद्दे को भी उठाया। उद्यमियों ने जैन से बवाना में उद्योग फ्री होल्ड करने की भी मांग की। उद्यमियों की मांग पर जैन ने आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनने पर उद्यमियों को भी बिजली बिलों में राहत और सर्कल दरों को तर्कसंगत बनाने के साथ ही उद्योग फ्री होल्ड करने का भी भरोसा दिया।

दिल्ली सरकार ने पिछले साल घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के माध्यम से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर राहत दी थी। इसके अलावा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2019-20 के टैरिफ में इससे पहले वाले वर्ष फिक्स चार्ज में की गई भारी वृद्धि में कमी कर राहत दी थी। लेकिन उद्योग के लिए बिजली दरें 7.25 रुपये यूनिट से बढ़ाकर 7.75 रुपये यूनिट कर दी थी। साथ ही उद्योग के लिए फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी को बरकरार रखा, जिससे उद्यमी पर बिजली बिल का बोझ बढ़ गया है।

डीजल कॉम्पैक्ट सिडैन में हुंडई का धमाका

बीएस-6 डीजल इंजन वाली ऑरा उतारकर मारुति डिजायर को देगी टक्कर

ऋषभ कृष्ण सक्सेना
नई दिल्ली, 21 जनवरी

नामी कार कंपनी हुंडई ने भारतीय बाजार में आज अपनी नई कॉम्पैक्ट सिडैन ऑरा पेश कर दी। इससे कार बाजार में हलचल मचना तय है क्योंकि ऑरा देश में भारत स्टेज-6 (बीएस-6) डीजल इंजन वाली पहली सिडैन है। सबसे बड़ी देसी कार कंपनी मारुति सुजूकी समेत कोई भी अन्य कंपनी फिलहाल 4 मीटर से कम लंबाई वाली बीएस-6 डीजल सिडैन नहीं बेच रही है।

ऑरा की कीमत के जरिये हुंडई ने कॉम्पैक्ट सिडैन बाजार में मुकाबले का नया बिगुल फूंक दिया है क्योंकि इसकी कीमत इस श्रेणी की नंबर एक कार डिजायर से भी कम रखी गई है। ऑरा की कीमत 5.80 लाख रुपये से शुरू हो रही है, जबकि मारुति की डिजायर 5.83 लाख रुपये से शुरू होती है। इसी श्रेणी में होंडा कार्स इंडिया की अमेज का दाम 5.93 लाख रुपये से शुरू होता है। ऑरा के डीजल मॉडल का दाम लगभग 7.74 लाख रुपये से शुरू है।

नई दिल्ली में मंगलवार को नई कॉम्पैक्ट सिडैन पेश करते हुंडई मोटर इंडिया के एमडी व सीईओ एसएस किम। *फोटो : संजय शर्मा*

- देश में बीएस-6 डीजल इंजन में पहली कॉम्पैक्ट सिडैन है ऑरा
- पेट्रोल मॉडल **5.80** लाख और डीजल मॉडल **7.73** लाख रुपये से शुरू
- **1.0** लीटर टर्बो इंजन और सीएनजी में भी की गई पेश
- इस श्रेणी में सर्वाधिक बिकने वाली कार है मारुति डिजायर
- लेकिन मारुति ने किया छोटे बीएस-6 डीजल इंजन लाने की संभावना से इनकार

हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी एसएस किम ने ऑरा पेश करते हुए कहा कि कॉम्पैक्ट डीजल कार का बाजार एक तरह से हुंडई के लिए ही रह जाएगा क्योंकि अभी तक किसी अन्य कंपनी ने ऐसा इंजन लाने का ऐलान नहीं किया है। होंडा और फोर्ड इंडिया बीएस-6 इंजन वाली कॉम्पैक्ट सिडैन पेश तो करेंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने तारीखों का ऐलान नहीं किया है। मारुति के साथ ही टोयोटा किर्लोस्कर, टाटा मोटर्स, रेनो इंडिया जैसी कंपनियां इससे इनकार कर चुकी हैं।

ऐसी सूरत में हुंडई डिजायर और अमेज के साथ ही फोर्ड की एस्पायर के बाजार में भी सेंध लगाने की कोशश करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा तपिश मारुति को झेलनी पड़ सकती है। मारुति की डिजायर इस बाजार में छाई हुई है। पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच 52,514 डिजायर बिकी थीं, जबकि हुंडई अपनी मौजूदा कॉम्पैक्ट सिडैन एक्सेंट की केवल 4,139 इकाई ही बेच पाई थी।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

कैन फिन होम्स

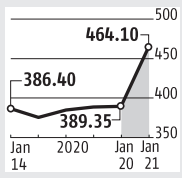

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 20 फीसदी बढ़ा

₹ 389.35 पिछला बंद भाव
₹ 464.10 आज का बंद भाव
▲ 19.20 %

टाटा स्टील

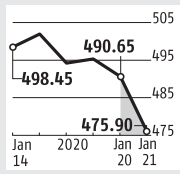

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 490.65 पिछला बंद भाव
₹ 475.90 आज का बंद भाव
▼ 3.01 %

स्पेंसर्स रिटेल

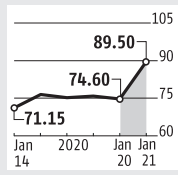

राधाकिशन एस धमानी ने दिसंबर तिमाही में ली 2.09 फीसदी हिस्सेदारी

₹ 74.60 पिछला बंद भाव
₹ 89.50 आज का बंद भाव
▲ 20.00 %

ग्रैन्यूल्स इंडिया

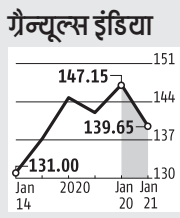

बोर्ड ने 200 रुपये प्रति शेयर भाव पर पुनर्खरीद को दी मंजूरी

₹ 147.15 पिछला बंद भाव
₹ 139.65 आज का बंद भाव
▼ 5.10 %

केईआई इंडस्ट्रीज

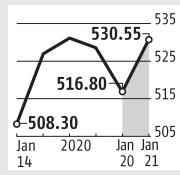

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 29 फीसदी बढ़ा

₹ 516.80 पिछला बंद भाव
₹ 530.55 आज का बंद भाव
▲ 2.66 %

संक्षेप में

आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का शुद्ध लाभ स्थिर

निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का शुद्ध लाभ दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 302 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा। कंपनी की नए कारोबार से आय में 33 फीसदी वृद्धि के बावजूद लाभ स्थिर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के बयान के अनुसार नए कारोबार से उसकी आय दिसंबर, 2019 तिमाही में 33 फीसदी बढ़कर 426 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 320 करोड़ रुपये थी। कंपनी का शुद्ध लाभ आलोच्य तिमाही में 302 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 2018-19 की इसी तिमाही में 297 करोड़ रुपये रहा था। *भाषा*

ऐक्सिस-कार्वी मामले पर यथास्थिति बरकरार

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने ऐक्सिस बैंक और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग मामले में 31 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 15 जनवरी को ऐक्सिस बैंक ने सेबी के आदेश के खिलाफ राहत पाने के लिए सैट का दरवाजा खटखटाया था। सेबी ने कहा था कि पूर्ण भुगतान वाले क्लाइंटों के शेयरों को कार्वी की तरफ से गिरवी रखा जाना कानूनी रूप से अवैध था। *बीएस*

संजय कुमार की इंडिगो में बने मुख्य रणनीतिकार

इंडिगो छोड़कर एयर एशिया इंडिया में गए संजय कुमार की इंडिगो एयरलाइंस में वापसी हो रही है। उन्हें कंपनी के मुख्य रणनीतिकार एवं राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कुमार इंडिगो में वापस लौट रहे हैं। एयर एशिया इंडिया में जाने के लिए उन्होंने इंडिगो को छोड़ दिया था। *भाषा*

उबर ईट्स और जोमैटो में सौदा

पूरी तरह शेयर आधारित सौदे के तहत जोमैटो में उबर को मिलेगा 9.9 फीसदी हिस्सा

सुरजीत दास गुप्ता और नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 21 जनवरी

उबर इंडिया आज अपने ऑनलाइन फूड डिलिवरी कारोबार को बेच रही है और ऐसे में 4 अरब डॉलर के इस बाजार में केवल दो प्रमुख कंपनियों- स्विगी और जोमैटो- बची रहेंगी के बीच वर्चस्व की लड़ाई दिखेगी। लगातार बढ़ रहे घाटे के बीच महज सात महीने के भीतर सुदृढीकरण की यह पहल की गई है।

उबर ने भारत में अपनी प्रमुख प्रतिस्पर्धी ओला ने फूडपांडा को खरीदा था लेकिन बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उसने ऑनलाइन फूड डिलिवरी कारोबार को बंद कर क्लाउड किचन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया था। पूरी तरह शेयरों पर आधारित इस सौदे के तहत उबर को जोमैटो में 9.9 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी। विश्लेषकों के अनुसार इस सौदे का मूल्य 35 से 40 करोड़ डॉलर के बीच हो सकता है।

पिछले सात महीनों के दौरान इस कारोबार में सुदृढीकरण से दूरसंचार सेवा क्षेत्र की याद आती है जहां गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण ऑपरेटरों की संख्या 18 से घटकर महज 4 रह गई थी और वोडाफोन-आइडिया के बंद होने की आशंका है जिससे बाजार में केवल तीन कंपनियां बची रहेंगी।

रेडसीर के आंकड़ों के अनुसार, फूड डिलिवरी कारोबार के राजस्व में उल्लेखनी वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2019 में पिछले वर्ष के मुकाबले 150 फीसदी की वृद्धि हुई लेकिन अधिकतर मामलों में राजस्व के मुकाबले घाटे का आकार लगभग बराबर अथवा अधिक रहा।

ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट और आक्रामक प्रचार-प्रसार के कारण डिलिवरी लागत बढ़ गई जो घाटे की मुख्य वजह है। नकदी किल्लत झेल रही कंपनियां हमेशा ताजा दौर के निवेश के तहत रकम जुटाने पर ध्यान देने लगीं ताकि वृद्धि को रफ्तार दी जा सके। उदाहरण के लिए, उबर ईट्स के लिए पिछले तीन महीने के दौरान उसके सकल वैश्विक राजस्व में भारत का योगदान 3 फीसदी रहा और उसकी बाजार हिस्सेदारी 12 फीसदी हो चुकी है। जबकि दूसरी ओर, पिछली तीन तिमाहियों के दौरान उबर ईट्स के वैश्विक नुकसान में भारत का योगदान 25 फीसदी रहा जिससे कंपनी की लाभप्रदता पर काफी दबाव बढ़ गया।

यहां तक कि अलीबाबा के निवेश वाली कंपनी जोमैटो भी मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष कर रही है। मार्च 2019 में उसका घाटा 10 गुना बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये हो गया। जबकि इस दौरान कंपनी का राजस्व 188 फीसदी बढ़कर 1,397 करोड़ रुपये हो गया। फाइनैंशियल टाइम्स से बातचीत में मुख्य परिचालन अधिकारी गौरव गुप्ता ने कहा था कि कंपनी 2020 तक मुनाफे में आ जाएगी।

नैसपर के निवेश वाली कंपनी स्विगी की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। वित्त वर्ष 2019 में उसका घाटा 6 गुना बढ़कर 2,364 करोड़ रुपये हो गया लेकिन उसका राजस्व 177 गुना उछाल के साथ 1,297 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

विश्लेषकों का कहना है कि इस सौदे से जोमैटो एक ही झटके में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी और वह बाजार की अग्रणी कंपनी स्विगी से भी आगे निकल जाएगी। हाल में कंपनी ने ऐंट फाइनैंशियल से 15 करोड़ डॉलर जुटाए थे।

सुदृढ़ीकरण

- सौदे से भारत के फूड डिलिवरी क्षेत्र में दो प्रमुख खिलाड़ी जोमैटो और स्विगी बचेंगी
- जोमैटो का राजस्व वित्त वर्ष 2019 में तीन गुना बढ़कर 1,397 करोड़ रुपये हुआ
- वित्त वर्ष 2019 में जोमैटो का घाटा 10 गुना बढ़कर 1,001 करोड़ रुपये हुआ
- वित्त वर्ष 2019 में जोमैटो का कुल खर्च 3,598 करोड़ रुपये रहा

भारतीय नेविगेशन के साथ चिपसेट जारी

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 21 जनवरी

क्वालकॉम टेक्नोलॉजिज ने भारत की खुद की नेविगेशन प्रणाली- नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सटेलेशन (नेवआईसी) समर्थ चिपसेट जारी किए हैं। नेवआईसी अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की तरह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा है कि उसने क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन मोबाइल चिपसेट प्लेटफॉर्म को नेवआईसी दक्षता से समर्थ बनाने के लिए परामर्श मुहैया कराई है।

इसरो ने कहा, 'इस चिपसेट के जारी होने से स्मार्टफोन के मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा नेवआईसी के इस्तेमाल में तेजी आएगी। ओईएम अब भारतीय बाजार के लिए कोई भी नया मॉडल नेवआईसी समर्थ बनाएंगी और इस प्रकार नेवआईसी धीरे-धीरे नए हैंडसेट, ऐप्लिकेशन, प्रॉसेसर आदि का एक प्रमुख हिस्सा होगी। इससे नेवआईसी के कवरेज क्षेत्र के दायरे में स्मार्टफोन की भू-स्थिति दक्षता में भी सुधार होगा।'

क्वालकॉम इनकॉरपोरेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजिज ने इसरो के साथ मिलकर अपने आगामी पोर्टफोलियो के तहत चुनिंदा चिपसेट प्लेटफॉर्म के लिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस), नेवआईसी का विकास और परीक्षण किया है।

इस पहल से नेवआईसी का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभाओं की मदद से मोबाइल फोन एवं वाहन की भू-स्थिति दक्षता को बेहतर करने और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) समाधान तैयार करने में मदद मिलेगी। यह समाधान क्वालकॉम टेक्नोलॉजिज की प्रमुख प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अपडेटेड प्लेटफॉर्म के तहत क्वालकॉम लोकेशन सूट अब सात सेटेलाइट कॉस्टेलेशन को सपोर्ट करती है जिसमें नेवआईसी से संबंधित उपग्रह भी शामिल हैं।

इसरो के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के शिवन ने कहा, 'नेवआईसी देश के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की ओर उठाया गया हमारा एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हम इसे सब की दैनिक जिंगदी में इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए उत्सुक हैं।'

ऑटो एक्सपो: होंगे 70 से ज्यादा लॉन्च

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 21 जनवरी

वाहन क्षेत्र में सुस्ती के बावजूद 7 फरवरी से शुरू हो रहे द्विवर्षीय ऑटो एक्सपो 2020 में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा संख्या में नए वाहन लॉन्च होने की उम्मीद है। इस दौरान वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम के सदस्यों द्वारा लॉन्च किए जाने वाहनों की संख्या 70 से अधिक रहने की उम्मीद है। जबकि गैर-सायम सदस्य कंपनियां दर्जनों नई कार लॉन्च करेंगी। इनके द्वारा लॉन्च किए जाने वाले कुल वाहनों की संख्या भी पिछली वर्ष के मुकाबले अधिक रहेगी।

सायम के महानिदेशक राजेश मेनन का कहना है कि नए लॉन्च होने वाले वाहनों से ग्राहकों की धारणा में बदलाव आने की उम्मीद है जिससे बिक्री में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस बार सायम से नहीं जुड़ने वाली कंपनियां भी कई वाहन लॉन्च कर रही हैं जिससे यह संख्या बढ़ेगी। पिछले वाहन मेले में कुल 85 वाहन लॉन्च किए गए थे।

ग्रेटर नोएडा में आयोजित ऑटो एक्सपो 2020 आम जनता के लिए 7 से 12 फरवरी के बीच खुला रहेगा। इस दौरान वैश्विक कंपनियों द्वारा करीब 10 वाहनों को लॉन्च किया जाएगा जबकि भारतीय कंपनियों द्वारा 24 वाहन लॉन्च किए जाएंगे। जबकि इस दौरान 6 कॉन्सेप्ट वाहनों, 7 फेसलिफ्ट मॉडलों और 21 वाहनों की झलक दिखाने की योजना है।

हालांकि इनमें सबसे अधिक वाहन टाटा मोटर्स लेकर आएगी लेकिन ग्रेट मार्क तथा एमजी मोटर जैसी चीनी कंपनियों ने भी अपने लिए अलग-अलग 3,500 वर्ग मीटर क्षेत्र की बुकिंग कराई है।

डीजल कॉम्पैक्ट सिडैन में हुंडई का धमाका

पृष्ठ 1 का शेष...

मगर डिजायर की बिक्री में डीजल मॉडल की भी अच्छी-खासी हिस्सेदारी है, जो इस साल 1 अप्रैल से बाजार से गायब हो जाएंगे क्योंकि कंपनी ने अभी तक कम क्षमता वाले बीएस-6 डीजल इंजन बनाने से इनकार ही किया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मारुति भी जल्द ही छोटे डीजल इंजन लाएगी।

उद्योग के जानकारों को भी लगता है कि ऐसा करना कंपनी के लिए जरूरी होगा वरना उसे ग्राहकों का एक बड़ा तबका गंवाना पड़ सकता है। हालांकि मारुति ने अभी तक यही कहा है कि 1.2-1.3 लीटर डीजल इंजन को बीएस-6 मानक में ढालने पर कार की कीमत 1.3 लाख से 1.5 लाख रुपये तक बढ़ जाएगी, जो व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन बीएस-4 डीजल एक्सेंट और बीएस-6 डीजल ऑरा की शुरुआती कीमत में केवल 1 लाख रुपये का अंतर है।

पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर और लीडर (ऑटोमोटिव) कवन मुख्त्यार ने कहा, 'डीजल कॉम्पैक्ट सिडैन में कीमत कम रखना और मुनाफा कमाना आसान काम नहीं होता। लेकिन वैश्विक स्तर पर लंबे अरसे से काम कर रही कंपनियां ऐसा कर सकती हैं और कीमत वाजिब हो तो बिक्री होना तय है।'

किम मानते हैं कि इस कीमत के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने में ऑरा को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें इस साल बिक्री में इस कार के अच्छे-खासे योगदान की भी उम्मीद है। हालांकि उन्होंने कोई आंकड़ा देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि नई क्रेटा, ऑरा और दूसरे मॉडलों के साथ हुंडई की बिक्री इस साल काफी बढ़ जाएगी। फिलहाल यात्री कार बाजार का 17.3 फीसदी हिस्सा हुंडई के पास है, जबकि 2018 में उसकी हिस्सेदारी 16.3 फीसदी ही थी। कंपनी ऑरा के जरिये एक्सेंट से मिली निराशा दूर करेगी क्योंकि एक्सेंट की बिक्री बेहद सुस्त है और अब वह कैब के तौर पर ही खरीदी जा रही है। लेकिन कंपनी उसे बंद करने नहीं जा रही है।

किम ने यह भी मानने से इनकार कर दिया कि ऑरा की वजह से उनकी प्रीमियम हैचबैक ग्रैंड आई 10 नियॉस की बिक्री पर फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'दोनों श्रेणियों के ग्राहक एकदम अलग हैं। ऑरा की अलग खूबियां हैं और नियॉस अपनी तरह की अलग गाड़ी है। अभी तक की नियॉस की बिक्री देखकर नहीं लगता कि ऑरा से उसकी बिक्री पर किसी तरह का फर्क पड़ेगा।' हुंडई ने ऑरा को 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर डीजल के साथ 1.0 टर्बो पेट्रोल और सीएनजी इंजनों में भी पेश किया है।

अमेरिकी फर्मों को रिलायंस की टक्कर

एजेंसियां
नई दिल्ली, 21 जनवरी

बर्नस्टीन रिसर्च ने मंगलवार को कहा कि अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका की एक्सॉन, एटीऐंडटी तथा एमेजॉन को 'भारत का जवाब' कहा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, 'रिलायंस ने भारत के ऊर्जा तथा दूरसंचार क्षेत्र को करांतिकारी रूप से बदला है और यह रिटेल, फिनटेक तथा मीडिया क्षेत्र में भी इसी तरह के बदलाव ला रही है।' इसमें कहा गया है कि शोध, नवोन्मेष तथा इन्हें लागू करने के मामलों में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा है।

रिपोर्ट का कहना है कि तेल से लेकर दूरसंचार आदि क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनी रिलायंस का प्रमुख कारोबार अभी भी ऊर्जा क्षेत्र ही है और जिस तरह अगले दशक में भारत तेल तथा रासायनिक उत्पादों के मामलों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है, ऐसे में कंपनी इस क्षेत्र में अतिरिक्त विस्तार पर ध्यान दे सकती है। साथ ही, ब्रिटेन की बीपी तथा सऊदी आरामको के साथ साझेदारी से इस कदम को गति मिलेगी।

रिलायंस के पास विश्व का सबसे बड़ा सिंगल-साइट तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है और कंपनी के बहुत से पेट्रोकैमिकल प्लांट हैं। तीन साल पहले कंपनी ने दूरसंचार क्षेत्र में कदम रखा था और वर्तमान में इस क्षेत्र के कुल राजस्व में 34 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती है। बर्नस्टीन ने कहा, 'हालिया आंकड़ों के हिसाब से कहा जा सकता है कि यह अगले वित्त वर्ष के अंत तक 44 प्रतिशत हिस्सेदारी पर पहुंच सकती है।' खुदरा कारोबार के मामले में बर्नस्टीन का कहना है कि रिलायंस ऑफलाइन क्षेत्र की अहम कंपनी है जिसका 18.5 अरब डॉलर का राजस्व 11,000 से अधिक स्टोर से आता है। इसमें कहा गया, 'नए क्षेत्रों में कंपनी अच्छी स्थिति में है और यह ई-कॉमर्स तथा फिजिकल स्टोर का डिजिटलीकरण कर रही है।'

शोध संस्था बर्नस्टीन रिसर्च का कहना है कि रिलायंस का भारत के ऊर्जा, दूरसंचार तथा रिटेल क्षेत्र में ठीक उसी प्रकार दबदबा है जिस तरह एक्सॉन, एटीऐंडटी और एमेजॉन का अमेरिका में है

इसके अलावा, फिनटेक क्षेत्र में भी रिलायंस अच्छी स्थिति में है और रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए किराना स्टोर का डिजिटलीकरण करना एवं जियो मनी ऐप के सहारे म्युचुअल फंड का वितरण नई कारोबारी संभावनाएं ला रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि मीडिया की विशिष्ट संभावनाओं तथा दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार के बाद डिज्नी तथा वायकॉम से साझेदारी करके रिलायंस भारत के विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म में अहम भूमिका निभाएगी।

बर्नस्टीन ने कहा, 'तेल एवं गैस, दूरसंचार, रिटेल, मीडिया तथा फिनटेक क्षेत्रों में प्रसार करने के साथ ही रिलायंस देश की सबसे विविध कंपनी बन गई है। इस तरह की कोई कंपनी नहीं है। भारत में रिलायंस का ऊर्जा, दूरसंचार तथा रिटेल क्षेत्र में ठीक उसी प्रकार दबदबा है जिस तरह एक्सॉन, एटीऐंडटी और एमेजॉन का अमेरिका में है लेकिन तीन अलग कंपनियां होने के बजाए रिलायंस ने इस तीनों के कारोबार को एक कंपनी के तौर पर ला दिया है।'

एक तरफ एक्सॉन विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली तेल एवं गैस कंपनी है, वहीं एटीऐंडटी विश्व की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है।

पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं के लिए अग्रिम शुल्क पर चली कैंची

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 21 जनवरी

बाजार नियामक सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजरों के लिए नियम मंगलवार को अधिसूचित कर दिया। इसके तहत क्लाइंटों से ली जाने वाली निवेश की न्यूनतम रकम दोगुनी कर 50 लाख रुपये कर दी गई है और ऐसे मैनेजरों को अपनी हैसियत इस अधिसूचना के तीन साल के भीतर 5 करोड़ रुपये करने को कहा है।

पीएमएस के तहत पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंटों को उनकी जरूरतों के सलाह की पेशकश करते हैं, जो मोटे तौर पर धनाढ्य निवेशक होते हैं। नियामक ने पोर्टफोलियो मैनेजरों से कहा है कि वे क्लाइंटों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अग्रिम शुल्क न वसूले। साल 2018 में सेबी ने म्युचुअल फंडों के लिए ऐसा ही नियम बनाया था और अग्रिम कमीशन पर पाबंदी लगा दी थी। एमएफ उद्योग से कहा गया था कि वह कमीशन भुगतान के मामले में पूरी तरह से निवेश को आधार बनाए।

यह वितरकों को प्रभावित करेगा क्योंकि अग्रिम कमीशन का एक हिस्सा प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें दिया जाता था। पीएमएस शुल्क के ढांचे में मोटे तौर पर 2-2.5 फीसदी अग्रिम कमीशन और पहले साल एकमुश्त शुल्क शामिल होता है। इस शुल्क में सालाना तय शुल्क की वसूली या तय व वेरिएबल शुल्क का संयोजन होता है, जो मुनाफे के प्रतिशत के तौर पर होता है।

पोर्टफोलियो मैनेजर अब सिर्फ डायरेक्ट प्लान के जरिये म्युचुअल फंडों की यूनिट में निवेश कर सकते हैं और वितरण से जुड़ा शुल्क ऐसी योजना में क्लाइंटों से नहीं वसूला जा सकता। इससे निवेशकों को लाभ होगा क्योंकि उनका खर्च घटेगा। नियामक ने पोर्टफोलियो मैनेजरों से कहा है कि वे डेरिवेटिव में निवेश के लिए क्लाइंटों के पोर्टफोलियो का इस्तेमाल न करे और सटोरिया लेनदेन में शामिल न हों, जिसके साथ वास्तविक डिलिवरी न हो (डेरिवेटिव कारोबार को छोड़कर)। यह कदम बाजार में उतारचढ़ाव कम करने के इरादे से उठाया गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अनुचित जोखिम पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंटों के फंड का इस्तेमाल बिल डिस्काउंटिंग, बदला फाइनैंसिंग या उधारी आदि में नहीं कर पाएंगे।

डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजरों को असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश से रोक दिया गया है। जो गैर-डिस्क्रिशनरी या सलाहकारी सेवाओं की पेशकश करते हैं वे ऐसी असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में क्लाइंटों की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का 25 फीसदी का निवेश कर सकेंगे या फिर इसकी सलाह दे पाएंगे।

पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंटों के फंड का निवेश किसी अन्य इकाई की सलाह के आधार पर नहीं कर पाएंगे। एक वरिष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर ने कहा, मैं निवेश सलाह आउटसोर्स नहीं कर सकता। शोध की क्षमता अब कंपनी के भीतर रखनी होगी, जिसका मतलब यह है कि छोटे पीएमएस या एक व्यक्ति वाला दुकान मुश्किल में घिरेगा। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ विकास सचदेव ने कहा, चूंकि अच्छे निवेशकों के लिए पीएमएस लगातार पसंदीदा बनता जा रहा है, ऐसे में ये नियम उस ढांचे को मजबूत बनाएंगे, जिसके दायरे में वे परिचालन करते हैं।

नए नियम

- **क्लाइंटों से ली जाने वाली निवेश की न्यूनतम रकम दोगुनी कर 50 लाख रुपये की गई**
- **मैनेजरों को अपनी हैसियत इस अधिसूचना के तीन साल के भीतर 5 करोड़ रुपये करने को कहा गया है**
- **पोर्टफोलियो मैनेजरों से कहा गया है कि वे क्लाइंटों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अग्रिम शुल्क न वसूले**

तीसरी तिमाही में 47,000 रुपये पर पहुंची कर्ज बिक्री : इक्रा

नकदी का दबाव एनबीएफसी को संपत्ति बिक्री के लिए लगातार बाध्य कर रहा है

अभिजित लेले
मुंबई, 21 जनवरी

दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में बिके 47,000 करोड़ रुपये के कर्ज में वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों की अहम हिस्सेदारी रही क्योंकि उनमें से कुछ के लिए नकदी की चुनौतियां जारी रही।

रेटिंग एजेंसी इक्रा के उपाध्यक्ष और प्रमुख (स्ट्रक्चर्ड फाइनैंस रेटिंग्स) अभिषेक डाफ्रिया ने कहा, तीसरी तिमाही में वॉल्यूम अक्टूबर-दिसंबर 2018 के अनुमानित 77,800 करोड़ रुपये के मुकाबले कम रहा। लेकिन पिछले साल की तीसरी तिमाही थोड़ी अलग रही क्योंकि वित्तीय व्यवस्था में नकदी संकट था, जो आईएलऐंडएफएस के डिफॉल्ट से प्रभावित हुआ।

डीएचएफएल जैसी बड़ी कंपनियां तीसरी तिमाही में बाजार में अच्छा खासा रकम जुटाने के लिए थीं। अब एनबीएफसी व एचएफसी के लिए स्थिति सुधरी है। लेकिन कुछ वित्तीय कंपनियों के लिए अभी भी परेशानी है क्योंकि बैंक उन्हें सीधे रकम देने के बजाय उनका लोन पोर्टफोलियो खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

इक्रा के अनुमान के मुताबिक, पिछले नौ महीने में पीटीसी लेनदेन वॉल्यूम करीब 64,000 करोड़ रुपये का रहा जबकि वित्त वर्ष 2019 की समान अवधि में यह करीब 71,000 करोड़ रुपये था। डीए लेनदेन इस अवधि में 93,000 करोड़ रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 1,28,000 करोड़ रुपये रहा था।

तीसरी तिमाही में वॉल्यूम हालांकि ज्यादा रहा, लेकिन एनबीएफसी के खातों की रफ्तार में सुस्ती के कारण बाजार ने कुछ मुश्किलों का सामना किया, जिसने बिक्री के लिए उपलब्ध पात्र संपत्तियों में कमी हुई।

रेटिंग एजेंसी ने कहा, इसके बाद भी कुछ और चीजें बाजार में वॉल्यूम को सहारा दे सकती हैं। एनबीएफसी और एचएफसी की नकदी की चुनौतियां उन्हें अपनी लोनबुक का कुछ हिस्सा बेचने के लिए बाजार में उतारेंगी। दूसरा, सरकार ने आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार किया है। अंत में, एनबीएफसी व एचएफसी के लिए न्यूनतम निवेशित अवधि के नियम में रियायत से प्रतिभूति बाजार को सहारा मिलेगा।

इश्यू के वॉल्यूम के लिहाज से भारतीय प्रतिभूतिकरण बाजार एक और अच्छे साल से दो चार हो रहा है। एनबीएफसी और एचएफसी रकम जुटाने के लिए और नकदी व संपत्ति देनदारी के बेमेल का प्रबंधन करने के लिए प्रतिभूतिकरण पर काफी ज्यादा भरोसा कर रही हैं। डाफ्रिया ने कहा, वित्त वर्ष 2020 में प्रतिभूतिकरण का बाजार दो लाख करोड़ रुपये के पार निकलने की संभावना है। वित्त वर्ष 2019 में यह 1.97 लाख करोड़ रुपये का रहा था।

एफएमसीजी उद्योग की पटरी पर लौटने की आस

पृष्ठ-1 का शेष

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, 'कृषि की जीडीपी के बेहतर रहने के कारण अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण एफएमसीजी राजस्व की वृद्धि 11-12 फीसदी तक पहुंच सकती है जो 2019-20 में 8-9 फीसदी थी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकारी खर्च बढ़ने से ग्रामीण आय को फायदा मिल सकता है जिससे एफएमसीजी उत्पादों की मांग बढ़ेगी। शहरी क्षेत्रों में एफएमसीजी राजस्व के 8 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है।'

पर्सनल और होम केयर श्रेणी की रफ्तार 2020-21 में 8-9 फीसदी रहने की उम्मीद है जो 2019-20 में 6-7 फीसदी थी। एफएमसीजी की कुल बिक्री में इसकी एक तिहाई हिस्सेदारी है।2019 में ग्रामीण बाजार में सुस्ती से अधिकांश एफएमसीजी कंपनियां प्रभावित हुई थीं। जुलाई-सितंबर 2018 में एफएमसीजी क्षेत्र की बिक्री वृद्धि करीब 16 फीसदी थी जो दिसंबर 2019 तिमाही में केवल 2.1 फीसदी रह गई। इससे पूरे एफएमसीजी क्षेत्र की बिक्री दर गिरकर 3.5 फीसदी रह गई। पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री में केवल 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी जो 2018 में 13 फीसदी थी। इस बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर सितंबर तिमाही में घटकर 4.5 फीसदी रह गई। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान में कटौती की है। इसके अब 4.8 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। नीलसन का मानना है कि वृहद आर्थिक कारक अब भी अनुकूल नहीं है लेकिन 2019 की अंतिम तिमाही में एफएमसीजी की वृद्धि पटरी पर लौट सकती है।

एचडीएफसी एएमसी का मुनाफा बढ़ा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 21 जनवरी

देश की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) ने दिसंबर तिमाही में 466 करोड़ रुपये का कर पूर्व मुनाफा किया जो पिछले साल की समान अवधि से 27 फीसदी अधिक है।

वित्त वर्ष के पहले नौ महीने के दौरान कंपनी का कर पूर्व मुनाफा 38 फीसदी की बढ़त के साथ 1,323 करोड़ रुपये रहा। 3.68 लाख करोड़ रुपये की इस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी दिसंबर के अंत में 14.4 फीसदी थी।

कंपनी की फीस और कमीशन लागत में दिसंबर तिमाही में भी कमी दिखी। इस दौरान उसका खर्च पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 87 फीसदी की कमी के साथ 71 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का इक्विटी ऑरिएंटेड और गैर-इक्विटी ऑरिएंटेड एसेट अंडर मैनेजमेंट का अनुपात 46:54 था जबकि उद्योग का अनुपात 41:59 था। इक्विटी उत्पादों के अनुपात में सुधार कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत है क्योंकि निश्चित आय उत्पादों की तुलना में इक्विटी उत्पादों में ज्यादा प्रबंधन फीस मिलती है।

2019 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा वैश्विक डेरिवेटिव कारोबार

डेरिवेटिव कारोबार के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा भारत का नैशनल स्टॉक एक्सचेंज

समी मोडक
मुंबई, 21 जनवरी

वैश्विक एक्सचेंजों पर संयुक्त रूप से वायदा एवं विकल्प (एफऐंडओ) कारोबार साल 2019 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, ऐसा साल जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ट्वीट के चलते बाजार में उतारचढ़ाव रहा।

उद्योग निकाय फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन (एफआईए) के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव बाजार 13.7 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ साल 2019 में अब तक के सर्वोच्च स्तर 34.5 अरब अनुबंध पर पहुंच गया। डेरिवेटिव अनुबंध की संख्या के लिहाज से भारत का नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) वैश्विक स्तर पर सबसे आगे रहा। उसने अमेरिका के सीएमई समूह को पीछे छोड़ दिया जबकि वह कई सहायक एक्सचेंजों मसलन शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज और न्यू यॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज का परिचालन करता है। देश के सबसे बड़े एक्सचेंज में करीब 6 अरब एफऐंडओ अनुबंधों की ट्रेडिंग हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 57 फीसदी ज्यादा है। एफआईए के आंकड़े बताते हैं कि सीएमई पर कुल 4.8 अरब अनुबंधों की ट्रेडिंग हुई।

साथ ही साल 2019 के आखिर में वैश्विक स्तर पर कुल खड़े सौदे (ओपन इंटरेस्ट) 90 करोड़ अनुबंध रहे, जो एक साल पहले की तुलना में 9 फीसदी ज्यादा है।

भारत में ट्रेडिंग की गतिविधियां उतारचढ़ाव में इजाफे से भी प्रभावित हुईं, जिसकी वजह वैश्विक व देसी कारण थे। बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स का जीवाईरेट साल के दौरान 17 फीसदी रहा।

ट्रेडिंग वॉल्यूम का उतारचढ़ाव से काफी सह-संबंध होता है और यह उतारचढ़ाव चीन के खिलाफ ट्रंप के लगातार ट्वीट के कारण देखने को मिला, जिससे अक्सर वित्तीय बाजार प्रभावित हुआ।

आर्थिक व आय की रफ्तार में कमी और एनबीएफसी संकट ने निवेशकों को पिछले साल निवेशकों को परेशान किया। हालांकि बाजारों ने ज्यादातर अवरोध से बाहर निकलने में कामयाबी पाी, जिसकी वैश्विक स्तर पर नकदी की सहजता रही। साथ ही सितंबर में सरकार की तरफ से कंपनी कर में कटौती से भी इक्विटी बाजार को मजबूती मिली। इस बीच, वैश्विक स्तर पर चीन के साथ कारोबारी युद्ध पर ट्रंप की टिप्पणी से उतारचढ़ाव में इजाफा हुआ। संवेदनशील मसलों मसलन शेयर बाजार का स्तर, मौद्रिक नीति और व्यापार सौदों को लेकर ट्रंप ने शायद ही ट्वीट नहीं किया।

जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने वोल्फेफे इंडेक्स विकसित कर लिया (ट्रंप के 2017 के ट्वीट में इस्तेमाल किए गए रहस्यात्मक शब्द कोवफेफे पर आधारित)। इंडेक्स ने बाजार में उतारचढ़ाव पर राष्ट्रपति के ट्वीट के असर का अनुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक विकसित कर ली।

केआर चोकिसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रबंध निदेशक देवेन चोकसी ने कहा, उताचढ़ाव की कई वजह रही और वॉल्यूम में बढ़ोतरी अल्गो के बढ़ते इस्तेमाल और मशीन आधारित ट्रेडिंग के कारण हुई।

एक बयान में एनएसई ने वॉल्यूम में उछाल की वजह इक्विटी बाजार की गहराई को बताया। एनएसई के प्रबंध निदेशक व सीईओ विक्रम लिमये ने कहा, एनएसई ने पिछले पांच साल में नकदी क्षेत्र में 1.2 करोड़ नए निवेशकों का पंजीकरण देखा है, जिसमें से 87 लाख पिछले तीन साल में आए। यह भी पाया गया कि एक तिहाई नए निवेशक टियर-3 व टियर-4 शहरों से आए। इसके अलावा निवेशकों ने डिजिटल का इस्तेमाल किया और नकदी में 26 फीसदी कारोबार मोबाइल व इंटरनेट ट्रेडिंग के जरिए हुआ।

एफआईए के आंकड़ों के मुताबिक, डेरिवेटिव वॉल्यूम के लिहाज से बीएसई (गिफ्टी सिटी में इंडिया इंटरनैशनल एक्सचेंज समेत) का स्थान 13वां रहा, वहीं एमसीएक्स का 18वां। एफआईए ने 34 देशों में परिचालित 80 एक्सचेंजों के वॉल्यूम व ओपन इंटरेस्ट का विश्लेषण किया।

डेरिवेटिव कारोबार

- **वैश्विक स्तर पर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव बाजार 13.7 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ साल 2019 में अब तक के सर्वोच्च स्तर 34.5 अरब अनुबंध पर पहुंच गया**
- **डेरिवेटिव अनुबंध की संख्या के लिहाज से एनएसई) वैश्विक स्तर पर सबसे आगे रहा। उसने अमेरिका के सीएमई समूह को पीछे छोड़ दिया**

बीएस बातचीत

साल 2020 में नहीं मिलेगा उम्दा रिटर्न

अर्थव्यवस्था में कमजोरी के बावजूद बाजार आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टेक के उप-प्रमुख (इक्विटी-भारत) **मुकुल कोछड़** ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अवरोध से जिन कंपनियों को फायदा मिल रहा है वही बाजार को आगे बढ़ा रही हैं। **समी मोडक** को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एकीकरण और आयात इस साल का मुख्य थीम होगा। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश..

.अर्थव्यवस्था की दिशा और बाजार के प्रदर्शन की व्याख्या आप कैसे करेंगे?

बाजार उन शेयरों और क्षेत्रों की दम पर आगे बढ़ रहा है जिसे अर्थव्यवस्था में अवरोध का फायदा मिल रहा है। ये कंपनियां एकीकृत हो रही हैं, बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं और उनकी लाभप्रदता में इजाफा हो रहा है क्योंकि प्रतिस्पर्ध घटी है। विगत में पूंजी तक आसान और अव्यवस्थित पहुंच से बैंकिंग, सीमेंट, स्टील और निर्माण क्षेत्र में अतार्किक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। ये चीजें इन क्षेत्रों को पूंजी की लागत भी हासिल नहीं करने दे रही थी। हमारा शोध बताता है कि पूंजी पर रिटर्न में सुधार साल 2016-17 से विभिन्न क्षेत्रों में दिखना शुरू हो गया था। यह बताता है कि आज कंपनियां अपनी पूंजी लागत के मुकाबले ज्यादा वैल्यू जोड़ रही है, जो उनके शेयरों का प्रदर्शन बेहतर बना रहा है।

आपकी नजर में क्या बाजार यह मानकर चल रहा है कि आय और आर्थिक रफ्तार के अलावा लाभ सुस्त रह सकता है? साल 2020 में बाजार का परिदृश्य कैसा होगा?

सामान्य तौर पर यह बताना मुश्किल है कि बाजार क्या मानकर चल रहा है, लेकिन हम शेयरों के चयन में बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं देख रहे हैं। बाजार को लेकर हमारा नजरिया रचनात्मक है और हमारा मानना है कि दो अंकों में रिटर्न रह सकता है, लेकिन उसका स्तर निचला रहेगा।

ज्यादातर वैश्विक विश्लेषक कह रहे हैं कि इक्विटी के माहौल अनुकूल है। क्या आप इस राय को समर्थन देते हैं?

पिछला साल खास तौर से वैश्विक इक्विटी बाजारों के लिए अच्छा रहा। ऐसी मजबूती के बाद आगे चुनौती रह सकती है क्योंकि मजबूत वर्ष में कुछ रिटर्न मोटे तौर पर मूल्यांकन की दोबारा रेटिंग के जरिए सृजित होता है। कैलेंडर वर्ष 2019 इससे अलग नहीं था क्योंकि ज्यादातर बाजारों ने मूल्यांकन में विस्तार देखा। इसलिए सामान्य तौर पर 2020 का रिटर्न कम रह सकता है। भारत के बारे में हमारा मानना है कि 2019 के अच्छे रिटर्न के बाद निवेशकों को 2020 में इक्विटी जोखिम का पर्याप्त इनाम मिलेगा। इक्विटी का अनुकूल माहौल मोटे तौर पर सकारात्मक इक्विटी निवेश में परिवर्तित होता है और साल 2020 उससे अलग नहीं होगा।

लंबे समय के बाद इस साल अब तक व्यापक बाजारों ने लार्जकैप से बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या यह प्रवृत्ति टिकाऊ होगी?

जहां तक छोटी कंपनियों की बात है, हम निवेशकों को चयनात्मक रुख अपनाने की सलाह दे रहे हैं। प्रबंधन की गुणवत्ता और संचालन पर पूंजी बाजार काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, जो छोटी कंपनियों में मजबूत व व्यापक तेजी में अड़चन डालेगा, जैसी कि 2014 से 2018 तक तेजी देखी गई थी। छोटी कंपनियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली प्रबंधन टीम की नियुक्ति चुनौतीपूर्ण होती है।

अगले वित्त वर्ष के लिए आय का क्या पूर्वानुमान है? कौन सी चीजें आय को रफ्तार देंगी?

हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2020 में 15 फीसदी और वित्त वर्ष 2021 में 20 फीसदी अनुमानित आय हासिल की जा सकती है। कर की दरों में कटौती आय के चक्र में सुधार में मददगार रहा है।

भुगतान पर एकमत नहीं दूरसंचार फर्में

पृष्ठ-1 का शेष

शुरुआत में कुछ दूरसंचार कंपनियां तय समयसीमा से पहले 20 फीसदी राशि चुकाने की संभावना तलाश रही थी क्योंकि भुगतान नहीं करने की स्थिति में दूरसंचार विभाग उनकी बैंक गारंटी को भुना सकता है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कंपनियों की नई याचिका को स्वीकार करते हुए उसे अगले हफ्ते किसी समय सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही। इस पर सुनवाई उसी पीठ द्वारा की जाएगी जिसने दूरसंचार कंपनियों की समीक्षा याचिका को खारिज किया था। एक दूरसंचार कंपनी की प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सीए सुंदरम ने कहा कि वे भुगतान में किसी तरह की अड़चन नहीं चाहते हैं बल्कि भुगतान की नई समयसीमा की मांग कर रहे हैं।

कंपनियों ने खुली अदालत में सुनवाई पर जोर दिया लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस पर निर्णय संबंधित पीठ द्वारा किया जाएगा।पिछले साल 24 अक्टूबर को न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को 90 दिन के भीतर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के बकाये का भुगतान करने को कहा था। अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो इसे अदालत की अवमानना माना जा सकता है। अलबत्ता, एक दूरसंचार कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी की समयसीमा के बाद होनी है। उससे पहले दूरसंचार विभाग की तरफ से किसी तरह के दबाव की आशंका नहीं है।'

इसका मकसद न केवल एजीआर बकाये के भुगतान के लिए अधिक समय लेना है बल्कि दूरसंचार विभाग के साथ किस्तों में भुगतान के लिए मोलभाव भी करना है, बशर्ते न्यायालय इसकी अनुमति दे। इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए इसी तरह की अनुमति मिली थी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए यह अच्छी खबर है कि दूरसंचार कंपनियों को भुगतान के लिए ज्यादा समय मिल सकता है। कंपनी पर दूरसंचार विभाग का सबसे ज्यादा बकाया है और आशंका है कि भुगतान में राहत नहीं मिली तो कंपनी बंद हो सकती है। हालांकि कंपनी के वकीलों का कहना है कि कंपनी इस कारोबार में बने रहना चाहती है। आज कंपनी का शेयर 22.68 फीसदी की बढ़त के साथ 5.95 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि भारती एयरटेल के शेयर में 0.07 फीसदी की मामूली गिरावट आई और यह 508.35 रुपये पर बंद हुआ।

महंगी नहीं होगी विदेशी शराब

विदेशी शराब की खपत बढ़ी, सरकार का फिलहाल शराब पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार नहीं

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 21 जनवरी

इस समय केंद्र सरकार के सामने विदेशी अल्कोहल पर कुल मिलाकर आयात शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हवाईअड्डों पर शुल्क मुक्त शराब की खरीद की सीमा तय किए जाने के बारे में खबर आने के बाद सरकार के सूत्रों ने यह साफ किया है।

वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शराब उस सूची में शामिल नहीं है, जिन पर आयात शुल्क बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक वाणिज्य विभाग ने आगामी बजट में शुल्क मुक्त दुकानों से अल्कोहल के अलावा सिगरेट कार्टन खरीद पर भी प्रतिबंध लगाने का सुझाव वित्त मंत्रालय को दिया है।

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम गैर जरूरी सामान के आयात को हतोत्साहित करने के लिए हैं, लेकिन अभी भारी मात्रा में आयात शुल्क में बढ़ोतरी की योजना नहीं है। इसके बजाय सरकार खिलौनों, प्लास्टिक के सामान, स्पोर्ट्स के सामान और फर्नीचर जैसे 371 सामानों के आयात पर रोक लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिन्हें सरकार ने गैर जरूरी घोषित किया है।

अब ताजा सूचना से अल्कोहल के आयातकों को मानसिक राहत मिलेगी, जो इस अफवाह से चिंतित थे कि सरकार अल्कोहल की बिक्री सीमित करने पर विचार कर रही है।

इस समय वोदका, व्हिस्की और लिकर सहित अन्य स्ट्रॉग अल्कोहल पर 150 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगता है और उसके ऊपर अन्य शुल्क भी लगाए जाते हैं। वहीं बियर पर सीमा शुल्क 100 प्रतिशत है। पिछले दो साल के दौरान अल्कोहल का आयात बढ़ा है।

वहीं दूसरी ओर कन्फेडरेशन आफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरिज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने वाणिज्य विभाग को कई पत्र लिखे हैं और सरकार से मांग की है कि यूरोप से आने वाली वाइन पर आयात शुल्क न कम किया जाए। वहीं शुल्क कम किया जाना यूरोपीय संघ की प्रमुख मांग रही है, जिसे प्रस्तावित द्विपक्षीय कारोबार समझौते पर बातचीत के दौरान प्रमुखता से उठाया गया है। सरकार ने हाल ही में संकेत दिया था कि बारत शुल्क कम करने और यूरोप की वाइन और ऑटोमोबाइल की पहुंच भारत के बाजारों में बढ़ाने को इच्छुक है।

सीआईएबीसी की ओर से सरकार को लिखा गया पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड ने देखा है, जिसमें संगठन ने कहा है कि भारत में उत्पाद शुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे में भारत की कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें यह भी कहा गया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य पर माल की आवाजाही सीमित होने की वजह से भारत की कंपनियों को बड़ा बाजार बनाने में मुश्किल होती है और इसकी वजह से उत्पादन लागत घटाने में भी दिक्कत आती है।

उद्योग के सूत्रों के मुताबिक उद्योग का सालाना राजस्व 2,50,000 करोड़ रुपये है। सीआईएबीसी का कहना है कि यह उद्योग हर साल भारत सरकार के खजाने में 1,25,000 करोड़ रुपये देता है और कर में अंशदान करने वाले बड़े उद्योगों में से एक है। इसमें कहा गया है कि तमाम राज्य सरकारें इस उद्योग पर निर्भर हैं और उनके कुल कर संग्रह में इस उद्योग की हिस्सेदारी 20 से लेकर 40 प्रतिशत तक है।

पिछले साल प्रकाशित एक जर्मन अध्ययन के मुताबिक भारत में 2010 और 2017 के बीच अल्कोहल की खपत 38 प्रतिशत बढ़ी है। ड्रेसडेन युनिवर्सिटी आफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के अध्ययन के मुताबिक भारत में प्रति वयस्क शराब की सालाना खपत भी 4.3 लीटर से बढ़कर 5.9 लीटर हो गई है। प्रति व्यक्ति सालाना खपत अमेरिका में 9.8 लीटर और चीन में 7.4 लीटर है।

खूब छलके जाम : बढ़ा हर तरह की शराब का आयात

शराब	2017-18	2018-19
व्हिस्की	169.42	203.2
वाइन	25.28	28.2
ब्रांडी	18.7	21.5
जिन	18.1	21.1
मॉल्ट बियर	8.4	14.2
लिकर	7.47	8.41
रम	1.8	1.5

स्रोत : वाणिज्य विभाग — सभी आंकड़े 10 लाख डॉलर में

फ्रॉस्ट के खिलाफ मामला दर्ज

भाषा
नई दिल्ली, 21 जनवरी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 14 बैंकों के समूह के साथ 3,592 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के सिलसिले में मुंबई की कंपनी फ्रॉस्ट इंटरनैशनल, उसके निदेशकों उदय देसाई और सुजय देसाई के अलावा 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई बैंक ऑफ इंडिया के कानपुर जोन कार्यालय की शिकायत पर की गई है। बैंक का आरोप है कि निदेशकों का कोई वास्तविक कारोबार नहीं है फिर भी उन्होंने कर्ज लेने के लिए व्यापारिक गतिविधियों की आड़ ली। अधिकारियों ने कहा कि बैंक का आरोप है कि निदेशकों ने बैंक ऑफ इंडिया के अगुवाई वाले ऋणदाता बैंकों के समूह को भुगतान करने में चूक की है।

उन्होंने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों, जमानतदारों और अन्य अज्ञात लोगों ने फर्जी दस्तावेज जमा किए और बैंक से ली गई पूंजी की हेराफेरी कर उसे दूसरी जगह भेज दिया। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक के साथ 3,592.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

■ मुंबई की कंपनी फ्रॉस्ट इंटरनैशनल, उसके निदेशकों उदय देसाई और सुजय देसाई के अलावा 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज

कोलकाता की कंपनी की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने मंगलवार को बताया कि यह कुर्की धनशोधन रोकथाम कानून के तहत की गई है। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई कोलकाता की फेयर डील सप्लायर्स के निदेशकों के खिलाफ की गई। इसमें कंपनी की कोयंबटूर की भूमि और इमारत, अहमदाबाद में एक कार्यालय इमारत, एक फार्म हाउस, बंगला और सात सावधि जमा खातों को कुर्क किया गया है। इस पूरी संपत्ति का कुल मूल्य 107.73 करोड़ रुपये है। ईडी ने एक बयान में कहा कि कंपनी और उसके निदेशक राम प्रसाद अग्रवाल, नारायण प्रसाद अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, सौरभ झुनझुनवाला और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई के आरोप पत्र का अध्ययन करने के बाद ही ईडी ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पूर्व अधिकारी के खिलाफ मामला

सीबीआई ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के एक पूर्व संयुक्त निदेशक और एक निजी कंपनी के निदेशकों के खिलाफ 2014-15 के दौरान टर्मिनल उत्पाद शुल्क के फर्जी दावे के माध्यम से सरकारी खजाने को करीब 20.26 करोड़ रुपये का कथित रूप से चूना लगाने को लेकर मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बताया कि डीजीएफटी के पूर्व संयुक्त निदेशक (अहमदाबाद) एके सिंह और वहां की कंपनी क्रिस्टल क्रोप प्रोटेक्शन के निदेशकों मोहित कुमार गोयल, अंकुर अग्रवाल और नंद किशोर अग्रवाल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

हिचकोले खा रहे कर संग्रह से केंद्र सरकार की बढ़ रही है चिंता

सबकी नजरें चालू वित्त वर्ष की कर प्राप्तियों पर है, जिसका आगामी बजट में पुनरीक्षण होगा। ये आंकड़े बहुत अहम हो गए हैं क्योंकि वास्तविक कर संग्रह 2018-19 के अनुमान की तुलना में 1.91 लाख करोड़ रुपये कम रहने की संभावना है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के बजट में 2018-19 के वास्तविक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन पुनरीक्षित आंकड़े अंतरिम बजट में दिए गए हैं। वास्तविक आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़ों से 2018-19 में 1.68 लाख करोड़ रुपये कम रहे। 2018-19 के पुनरीक्षित राजस्व की तुलना में चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह में महज 9.47 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। बहरहाल इसका मतलब यह हुआ कि वित्त वर्ष 19 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 18.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले साल में भी शुरुआती कर संग्रह अनुमान की तुलना में वास्तविक संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये कम था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके लिए अपने पूर्ववर्ती वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दोषी करार दिया था, जिन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। बहरहाल अंतरिम बजट इस बार भाजपा सरकार के कार्यकाल में पीयूष गोयल ने पेश किया था।

केंद्र सरकार का कर राजस्व

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अंतर
2009-10	6.41	6.24	-0.17
2010-11	7.46	7.93	0.47
2011-12	9.32	8.89	-0.53,000
2012-13	10.78	10.36	-0.42
2013-14	12.36	11.39	-0.97
2014-15	13.64	12.44	-1.20
2015-16	14.49	14.56	0.70
2016-17	16.31	17.16	0.85

स्रोतः बजट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सभी आंकड़े लाख करोड़ रुपये में

ग्लोबल सिटी इंडेक्स में हैदराबाद 20 प्रमुख शहरों में

बीएस संवाददाता
बेंगलूरु, 21 जनवरी

नाइट फ्रैंक के ग्लोबल रेजिडेंशियल सिटीज इंडेक्स तीसरी तिमाही 2019 में शीर्ष 20 शहरों में भारत से एकमात्र हैदराबाद को जगह मिली है।

हैदराबाद में 2019 की तीसरी तिमाही में पिछले साल की तुलना में कीमतों में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह 15 शहरों में 14वें स्थान पर है। भारत के जिन अन्य शहरों में कीमतें बढ़ी हैं, उनमें नई दिल्ली वैश्विक रैंकिंग में 73वें स्थान पर है, जहां इस दौरान कीमतें 3.2 प्रतिशत बढ़ी हैं। बेंगलूरु 94वें स्थान पर, अहमदाबाद 108वें स्थान पर है। इस सूचकांक में हंगरी का शहर बुडापेस्ट पहले स्थान पर है, जहां कीमतों में 24 प्रतिशत तेजी आई है। वहीं चीन के श्यान और वुहान में क्रमशः 15.9 प्रतिशत और 14.9 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

हाल ही में आई वैश्विक संपत्ति सलाहकार जेएलएल इंडिया की सूची में सामाजिक-आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की रियल एस्टेट गतिविधियों के लिहाज से हैदराबाद दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर बनकर उभरा था। सूची में हैदराबाद पहले और बेंगलूरु दूसरे नंबर पर रहा। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद सूची में शीर्ष 20 शहरों में सात शहर भारत के थे।

बेंगलूरु में हो सकता है बड़ा जमीन सौदा

2,500 करोड़ की जमीन खरीदने के लिए ग्रेफाइट इंडिया से बात कर रहे रियल्टर

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 21 जनवरी

ऐंबेसी, आरएमजेड, प्रेस्टिज इस्टेट, सालारपुरिया सत्व सहित बेंगलूरु के कुछ शीर्ष डेवलपर और कनाडा के ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट, सिंगापुर के कैपिटलैंड जैसे कुछ बड़े पीई फंड कार्बन और ग्रेफाइट प्रोडक्ट विनिर्माता ग्रेफाइट इंडिया से कंपनी की 25 एकड़ जमीन खरीदने के लिए बात कर रहे हैं। यह जमीन बेंगलूरु के प्रमुख इलाके में है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

यह प्लॉट बेंगलूरु के ब्रुकफील्ड एरिया में है। सूत्रों ने बताया कि इस जमीन में 25 लाख वर्गफुट जगह विकसित की जा सकती है और खरीदार यहां बड़ा कार्यालय परिसर बना सकता है। सूत्रों ने कहा कि यह जमीन 2,000 करोड़ रुपये से 2,500 करोड़ रुपये के बीच में बिक सकती है।

सूत्र ने कहा, 'यह प्लॉट प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के करीब है और आउटर रिंगरोड से जुड़ी है। टेक जोन में विकास की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए कई शीर्ष डेवलपरों ने इस जमीन में दिलचस्पी दिखाई है।'

इस जमीन पर ग्रेफाइट की फैक्टरी थी, जो पिछले साल बंद हो गई।

एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंड इस प्लॉट की बिक्री का काम देख रही है। सूत्रों ने कहा कि अगर ऐंबेसी को यह जमीन मिल जाती है तो वह अपने साझेदार ब्लैकस्टोन से इसे खरीदने के लिए समझौता कर सकती है। सूत्रों ने कहा, 'ऐंबेसी, आरएमजेड, प्रेस्टिज इसमें दिलचस्पी ले रही हैं क्योंकि उनकी आसपास के इलाकों में बहुत संपत्तियां हैं।'

ग्रेफाइट इंडिया, आरएमजेड, ऐंबेसी, प्रेस्टिज, कैपिटलैंड को इस सिलसिले में भेजे गए मेल का कोई उचित जवाब नहीं मिला। ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट ने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है।

दिलचस्प है कि प्लॉट खरीदने को इच्छुक कंपनियों ने बीते दिनों धन जुटाया है। रिपोर्टों के मुताबिक आरएमजेड सीपीपीआईबी जापान की मित्सुई के साथ अपना पोर्टफोलियो बेचकर 3,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बात कर रही है। सिंगापुर की जीआईसी ने हाल ही में प्रेस्टिज में 434 करोड़ रुपये निवेश किया है। ब्लैकस्टोन के साथ ऐंबेसी के संयुक्त उद्यम ने पिछले साल देश के पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) के माध्यम से 4,750 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

सूत्रों ने कहा कि कैपिटालैंड आईटी पार्क सहित ऑफिस प्रॉपर्टीज का पोर्टफोलियो बनाने की इच्छुक है। सिंगापुर की सॉवरिन फंड जीआईसी और कैपिटालैंड हिनस रियल एस्टेट के साथ अलग अलग बात कर रही हैं, जो मुंबई के कंजुरमार्ग स्थित टाइल मेकर नित्को की डेवलपमेंट मैनेजर है। निक्टो की जमीन करीब 2,000 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए बातचीत चल रही है।

देश में सबसे ज्यादा बेंगलूरु में ऑफिस प्रॉपर्टी ली जाती हैं। 2019 में यहां करीब 150 लाख वर्गफुट जगह के सौदे हुए, जो 2018 की तुलना में 6 प्रतिशत ज्यादा है।

साल के दौरान टेक्नोलॉजी और आईटी-बीपीओ क्षेत्र ने कुल पट्टे में से 39 प्रतिशत लिया है, जिसके बाद इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की 16 प्रतिशत हिस्सेदारी है और फ्लैक्सिबल वर्कप्लेस की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है। साल के दौरान बेंगलूरु में आपूर्ति 109 लाख फुट बढ़ी है।

2019 में वाणिज्यिक संपत्ति के बड़े सौदे

खरीदार	विक्रेता	संपत्ति	मूल्य (करोड़ रु. में)
ब्लैकस्टोन	रेडियस	वन बीकेसी मुंबई	2,600
शपूरजी पलोनजी आलियांज	जीआईसी टिशमैन स्पेयर	वेवरॉक, हैदराबाद	1,800
सैंडर एनए	वेकफील्ड	आईटी सिटी इन्फो पार्क, पुणे	900
ब्लैकस्टोन	इंडियाबुल्स रियल एस्टेट	मुंबई व गुरुग्राम में संपत्तियां	810

स्रोतः कंपनियां व रिपोर्ट

प्रमुख औद्योगिक विकास की ओर वापसी के साथ डीपीआईआईटी ने मांगा ज्यादा धन

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 21 जनवरी

बजट आवंटन घटाए जाने के एक साल बाद उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने आगामी आम बजट में ज्यादा धन आवंटित करने की वकालत की है। विभाग ने पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी योजना के लिए अतिरिक्त धन की मांग की है।

विभाग को 2019-19 में 5,674.51 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2018-19 का पुनरीक्षित अनुमान 6,140.23 करोड़ रुपये था।

विभाग का आवंटन पिछले 5 साल में उतार चढ़ाव वाला रहा है। हर एक साल के अंतराल पर बजट बढ़ा या घटा है। लेकिन ई-कॉमर्स, खुदरा और कारोबार सुगमता व स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल के बाद विभाग अपने प्रमुख मकसद की ओर लौटा है। विभाग अब एकसमान देशव्यापी औद्योगिक विकास, खासकर पिछड़े व दूरस्थ इलाकों में औद्योगिक विकास की रणनीति पर काम कर रहा है।

एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा, 'स्टार्टअप इंडिया और कारोबार सुगमता, मेक इन इंडिया जैसी सरकार की प्रमुख योजनाओं पर शुरुआती जमीनी काम हो चुका है और इन क्षेत्रों में काम जारी है। लेकिन हमें अपने मूल एजेंडे पर वापस जाने की जरूरत है, जिसके तहत दूरस्थ इलाकों में औद्योगिक विकास कर ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मुहैया कराई जानी हैं।'

सरकार ने इस क्षेत्र में व्यय बहुत ज्यादा घटा दिया है। 2019-20 में इस क्षेत्र के लिए सरकार का बजट 909 करोड़ रुपये था, जो पहले के बजट के पुनरीक्षित अनुमान 1,707 करोड़ रुपये से बहुत कम है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब एक बार फिर यह केंद्र में आ गया है, जिसे देखते हुए विभाग ने ज्यादा धन दिए जाने का तर्क दिया है, जिससे जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे की जरूरतें पूरी की जा सकें। उन्होंने कहा कि डीपीआईआईटी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि औद्योगिक संवर्धन मेक इन इंडिया योजना के लिए और ज्यादा धन मुहैया कराया जाना चाहिए, जिस मद में 2019-20 में 473 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

साथ ही अधिकारियों ने यह उम्मीद जताई है कि पूर्वोत्तर इलाकों व हिमालय वाले राज्यों की औद्योगिक इकाइयों के केंद्रीय व एकीकृत जीएसटी वापसी के लिए धन आवंटन में बढ़ोतरी जारी रहेगी, जो 2019-20 में बढ़कर 1,700 करोड़ रुपये हो गया है।

साथ ही पहले के वर्षों की ही तरह विभाग को उम्मीद है कि स्टार्ट अप इंडिया और कारोबार सुगमता पर आवंटन बढ़ेगा, जिसके ई-बिज परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है।

दिसंबर तक के सरकार के अनुमान के मुताबिक स्टार्टअप इंडिया पहल से इसके 2016 में लागू किए जाने के बाद 2,85,890 नौकरियों का सृजन हुआ है। स्टार्टअप इंडिया में 25,000 से ज्यादा स्टार्टअप का पंजीकरण हुआ है। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति स्टार्टअप 11 से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां मिली हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने पाया है कि प्रत्येक प्रत्यक्ष रोजगार से 3 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है और परिणामस्वरूप इन स्टार्टअप से अनुमानित रूप से 5,60,000 से ज्यादा नौकरियों का सृजन हुआ है।'

बहरहाल यह आंकड़े स्टार्टअप की रिपोर्ट से आए हैं और सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। नौकरियों के सृजन पर सरकार ने मोटे तौर पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसका आवंटन नवंबर 2019 तक सरकार ने स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए किया है। स्टार्टअप की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए सराकर ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के तहत 2016 में 10,000 करोड़ रुपये के फंडों के फंड का सृजन किया था।

बीएस सूडोकू 3645

	5		2					1
8						6		
				3		5		9
1		4		6			9	
	8		3		9		4	
	9			4		8		7
2		5		1				
		1						3
3					2		1	

परिणाम संख्या 3644

8	7	2	5	4	9	1	3	6
5	6	9	1	3	2	8	4	7
4	3	1	8	6	7	5	9	2
1	5	7	2	9	3	6	8	4
3	2	4	6	5	8	7	1	9
9	8	6	7	1	4	3	2	5
7	9	5	3	2	1	4	6	8
6	4	3	9	8	5	2	7	1
2	1	8	4	7	6	9	5	3

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2000/2025, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4300/4350, तिल सफेद 8900/9100, सोया (टीन) 1550/1600, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1475/1575,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2010, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3350, चावल (सोना) 2900/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1405, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1475, फ्लैक 1428, डीएमओ 1012, टरपीन लैस बोल्ड 1500

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1200/1250, खुरपा 1100/1140,चाकू 1050/1150, रसकट 940/950, शक्कर 1200/1250, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3360, सिहोरा 3300, बुंदकी 3280, बुढ़ाना 3345,

हापुड़
गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1080/1125, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4300, खलः सरसों 2200/2300, बिनौला 2400/2550, चना छिलका 2190/2200,

जयपुर
अनाजः चावल डीबी 5500/5600, गेहूं (मिल) 2100/2110, मक्की 2200/2275, बाजरा 1920/1925, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 4500/4525,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3825, जौ 2130/2140,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7250/7300, बाजरा (गुजरात) 1900/1925, बाजरा (जयपुर) 1900/1925, चना 4200/4300, काबली चना 5000/6000, मूंग 6900/7000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)126, राइसब्रान (अखाद्य) 123, खल सरसों 1960, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1200, लाल 1200, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 7800/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7500/8500, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8800/9500, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5500,

अमृतसर
चावलः बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3750/3800, शरबती स्टीम 4100/4150,चावल 1509 सेला 5200/5225, धानः शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4140/4170, हरियाणा 4100/4120, राजस्थान 4060/4120, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2500/2600, सरसों खल 2080/2100,

फाजिल्का
गेहूं 2130/2140, सरसों 4300/4375 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4100/4110, कपास देशी 5050/5150, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2000/2060, चावल परमल कच्चा 2400/2425, से ला 2350/2375, मक्की यूपी 2175/2200, दाल उड़द छिलका 9200/10400, चना देशी 4900/5000, दाल चना 5100/5200, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600, चीन 8000/8500,

करनाल
गेहूं दड़ा 2020/2025, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2950/3000, पूसा 1509 धान 2850/2875, शरबती धान 2100/2150, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5250, स्टीम 6050/6150,

हिसार
ग्वार 3800/3850, जौ 1800/1810, सरसों 4050/4100, मूंग 6800/7000, गेहूं 2080/2100,

जींद
जीएसटी अतिरिक्तः गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1090, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 400/500, रिफाइंड (टीन) 1600/1620,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्तः सरसों 4150/4200, खल बिनौला मोटी 2300/2400, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 9050/9100, गेहूं 2150/2175, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1850/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 289

आबादी की समस्या

वर्षों तक आबादी में तेज वृद्धि भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भी समस्या बनी रही। परंतु हाल के वर्षों में इस समस्या का क्रम उलट गया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया के 27 देशों में अब 2010 की तुलना में कम आबादी है। 55 देश ऐसे हैं जहां 2050 तक आबादी में गिरावट आएगी। यानी जनसंख्या में कमी आना सामान्य बात हो जाएगी। इसके भू-आर्थिक परिणाम चिंतित करने वाले हैं। उदाहरण के लिए कुछ अर्थशास्त्री जिनके मुताबिक प्रतिव्यक्ति आर्थिक वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है और इसमें नवाचार की भूमिका होती है। उन्हें आशंका है कि आबादी कम होने से नवाचार में कमी आएगी। इससे प्रति व्यक्ति आय में ठहराव आएगा। अन्य लोगों की चिंता है कि आबादी कम होने से भविष्य की मांग को लेकर उत्पादकों के अनुमान में भी कमी आएगी। इससे समेकित मांग और निवेश का संकट उत्पन्न हो सकता है। कुछ अन्य का कहना है कि इन प्रभावों के चलते भविष्य में प्रजनन दर में और कमी आ सकती है क्योंकि भविष्य की कठिनाइयों के चलते लोग शायद कम संतानोत्पत्ति करें।

आबादी में ठहराव को पहले केवल अमीर अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा जाता था लेकिन अब उसे मध्य आय वर्ग वाले देशों में भी देखा जाने लगा है। भारत के जो देश उच्च मध्य आय के स्तर पर हैं उनमें भी यह दिखाई पड़ रहा है। वर्ष 2019 की आर्थिक समीक्षा में देश के जनांकीय ढांचे पर एक अध्याय है जो आने वाले वर्षों में संदर्भ बिंदु बन सकता है।

इसमें अनुमान जताया गया है कि 2021 से 2041 के बीच दो दशक में देश की जनसंख्या वृद्धि 12 फीसदी तक होगी। परंतु यह बात विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच आबादी में और प्रजनन में होने वाली बढ़ोतरी के अंतर को छिपा जाती है। कुछ राज्य मसलन बिहार आदि की आबादी 25 फीसदी बढ़ेगी। दूसरे राज्यों मसलन आंध्र प्रदेश की आबादी में शायद ही कोई खास बढ़ोतरी दर्ज होगी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021 से 2041 के बीच उसकी आबादी में 3.4 फीसदी का इजाफा होगा। समीक्षा के अनुसार इस सदी के चौथे दशक तक तमिलनाडु की आबादी में कमी आने लगेगी। आयु में आ रही तब्दीली का प्रभाव इससे भी कहीं पहले महसूस किया जाने लगेगा। सन 2031 तक 11 राज्यों में कामकाजी आयु वाली आबादी कम होने लगेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो देश के नीति निर्माताओं को ऐसी स्थिति की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जहां देश का बड़ा हिस्सा स्थिर या घटी आबादी की समस्या से दो चार होगा।

मानव विकास सूचकांकों पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य केरल की आबादी सन 2001 से 2011 के बीच केवल 0.5 फीसदी बढ़ी। देश के उन हिस्सों से काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है जहां स्कूल जाने वाली आबादी उच्चतम स्तर पर है।

स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर इसका असर दिखने लगा है। समीक्षा के मुताबिक 2010 के दशक में दिल्ली को छोड़कर देश के हर प्रदेश में 50 से कम छात्रों वाली प्राथमिक शालाएं बढ़ी हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में भी सुधार करना होगा ताकि बुजुर्ग मरीजों को सेवा दी जा सके। इतना ही नहीं, इस घटनाक्रम के वृहद आर्थिक प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। भारत हमेशा यह अपेक्षा नहीं कर सकता है कि श्रम शक्ति की बढ़ी हिस्सेदारी की बदौलत वृद्धि को गति मिलेगी। ऐसे में इस संभावित रुझान का मुकाबला करने का केवल एक ही तरीका नजर आ रहा है। हमें अधिक से अधिक महिलाओं को कामकाजी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

अजय मोहंती

सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक वृद्धि

नागरिकता नियमों से केंद्र-राज्य तनाव, सामाजिक कलह और लोगों की जिंदगी में गतिरोध पैदा हो रहा है। इससे आर्थिक वृद्धि के भी खतरे में आने की संभावनाएं देख रहे हैं नितिन देसाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत जुलाई में जब अपना पहला बजट पेश किया था तो तमाम दूसरे विश्लेषकों की तरह इस लेखक ने भी आर्थिक चिंताओं की एक सूची तैयार की थी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में तीव्र गिरावट, राजकोषीय दबाव, दोहरी बैलेंस शीट की समस्याएं, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को पेश आ रही मुश्किलें, रोजगार सृजन की सुस्त रफ्तार, छोटी इकाइयों एवं कृषि क्षेत्र में व्याप्त तनाव, कारोबारी लड़ाइयां और वैश्विक वृद्धि चालकों में सुस्ती जैसे बिंदुओं को उस सूची में रखा गया था। लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं और कुछ समस्याएं तो और भी गंभीर हो गई हैं। हालांकि अब सरकार इन मुश्किलों की मौजूदगी स्वीकार करने के लिए कहीं अधिक तैयार है और खुद प्रधानमंत्री बजट प्रक्रिया की सीधी बागडोर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे यह सरकार अपनी आर्थिक नीति को दिशा देने में भी अर्थशास्त्र की तुलना में नाट्यशास्त्र पर अधिक यकीन करती है लिहाजा हम वृद्धि तेज करने के लिए नाटकीय एवं अप्रत्याशित उपायों की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस समय हमें क्या इसी की जरूरत है?

दीर्घावधि वृद्धि की बुनियाद निवेशकों के उस विश्वास पर टिकी होती है जो उन्हें देश के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश की स्थिरता को लेकर होता है। विदेशी निवेशकों के मामले में तो यह बात खास तौर पर सही है। इस मोर्चे पर हालात गत जुलाई के बाद काफी बदले हैं। देश का राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाने के लिए चलाए गए अभियान और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लाए जाने की चर्चाएं सत्ताधारी दल की तरफ से दी जा रही तमाम सफाई के बावजूद डर एवं संदेह पैदा कर रही हैं।

नागरिकता से संबंधित प्रस्तावों के खिलाफ दी जा रही दलीलें इसके आर्थिक प्रभावों पर आधारित न होकर संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार को दी जा रही चुनौती पर आधारित हैं। पिछले 70 साल से धर्मनिरपेक्ष भारत के ही तौर पर लोग इस देश को देखते रहे हैं। ऐसे में यह महज दुर्घटना नहीं है कि संप्रदायवाद के खिलाफ इस प्रतिरोध की अगुआई कर रहे युवा संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर रहे हैं।

संप्रदायवाद और भेदभाव के आरोपों पर जोर-शोर से चर्चा होती रही है। इसे देखने का एक तरीका यह है कि सीएए कानून उन कथित अवैध प्रवासियों पर लागू होगा जो 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। सीएए बुनियादी तौर पर आम-माफी देने वाला कानून है। पहले भी अवैध शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहे कई देशों ने उन्हें वापस न भेज पाने पर ऐसी छूट देकर नागरिकता दी है। अमेरिका ने भी 1986 में रीगन के कार्यकाल में ऐसी माफी दी थी। लेकिन सीएए कानून के जरिये दी जा रही छूट साफ तौर पर विभेदकारी है क्योंकि यह मुस्लिमों को छूट से बाहर कर देता है। अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इस कानून पर उच्चतम न्यायालय का रुख क्या होगा? लेकिन यह समझा जा सकता है कि इतने सारे लोग इस कानून को समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्यों मान रहे हैं? इस कानून ने केंद्र एवं कई राज्य सरकारों के बीच तनातनी की स्थिति भी पैदा कर दी है जो उच्च वृद्धि पथ के लिए जरूरी माने जाने वाले सहकारी संघवाद की संभावनाओं को सीमित करता है। जीएसटी परिषद में आम सहमति से फैसले लिए जाने की स्थापित परंपरा से अलग होने को इस दिशा में पहले संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। अगर केंद्र एवं राज्यों के बीच तनातनी की स्थिति और बिगड़ती है तो हम आर्थिक नीति के अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी संघवाद की सोच से भटकाव देख सकते हैं। यह निवेश निर्णयों के अलावा आर्थिक वृद्धि को भी प्रभावित करेगा।

नागरिकता निर्धारण संबंधी प्रस्तावों ने देश भर में छात्रों की अगुआई में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। प्रदर्शनों के प्रति अधिकारियों के कुछ हद तक एकतरफा रवैये और प्रदर्शनकारियों पर हिंसात्मक जवाबी हमलों के प्रति बरती जा रही सहिष्णुता सड़कों पर टकराव और हिंसा बढ़ने का सबब बन सकता है। ऐसी स्थिति सार्वजनिक अव्यवस्था का माहौल पैदा करेगी जिससे निवेशक पैसे लगाने को लेकर भयभीत होंगे। खासकर देश के उत्तरी राज्यों में करोड़ों नए रोजगार पैदा करने की जरूरत है।

नागरिकता संबंधी इन प्रस्तावों को लागू करने से जमीनी स्तर पर व्यापक गतिरोध पैदा होगा और अगर 2005 के बाद असम में लागू हुए एनआरसी के अनुभव को आधार बनाएं तो इस कवायद का खासा आर्थिक प्रभाव भी होगा। असम में एनआरसी लागू हुआ तो उससे देश की महज तीन फीसदी ही प्रभावित हुई लेकिन इसे अंजाम देने में करीब एक दशक का वक्त लग गया। इस काम में 50,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी लगे और 1,200 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत आई।

सरकार ने अब कहा है कि उसका एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन यह सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा रहा है और उसके तमाम नेता इस बात को पूरी शिद्दत से कहते आए हैं। बहरहाल डर यह है कि एनआरसी और एनपीआर एक ही काम अंजाम देने के लिए हैं और इनका वैसा ही असर होगा जैसा असम में एनआरसी लागू करने पर हुआ है।

बड़ी समस्या गरीब लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर है। इनमें से कई लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं पेश कर पाएंगे जिसके बाद उनकी जिंदगी भारत की नागरिकता साबित करने में ही उलझ जाएगी। अधिकार समूह राइट्स ऐंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) ने असम में एनआरसी से बाहर रखे गए लोगों के बीच एक छोटा सर्वेक्षण कर उन पर पड़े आर्थिक बोझ का जायजा लिया।

सर्वेक्षण में शामिल 62 लोगों ने नागरिकता विवाद से संबंधित सुनवाई में शामिल होने पर औसतन प्रति व्यक्ति 19,065 रुपये खर्च किए थे। यह हमारी औसत प्रति व्यक्ति आय का करीब 15 फीसदी है और एक गरीब व्यक्ति की आय का बड़ा हिस्सा है।

इस सर्वेक्षण के मुताबिक, उनमें से कई लोगों को इसके लिए अपनी कृषि भूमि गिरवी रखने, मवेशी और कृषि उपज/बगीचा बेचने, ऑटो रिक्शा जैसा आय का इकलौता साधन भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोगों को तो इसके लिए कर्ज भी लेना पड़ा।

इसके अलावा दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को एनआरसी सेवा केंद्र तक पांच-दस बार जाने से जुड़ी चुनौतियां भी थीं। इस सर्वेक्षण में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया जिन्हें अपने दम पर विदेशी अधिकरण में बचाव करना पड़ा जिस पर अमूमन एक-डेढ़ लाख रुपये तक का खर्च आया।

असम में 1994-2005 के दौरान गरीबी दर 52 फीसदी से कम होकर 34 फीसदी पर आ गई थी लेकिन उसके बाद एनआरसी प्रक्रिया शुरू होने पर यह राज्य गरीबी के खिलाफ जंग में पिछड़ने लगा। वर्ष 2012 में अधिकांश राज्यों ने 10 फीसदी तक का सुधार दिखाया था, वहीं असम की गरीबी दर में केवल दो फीसदी की गिरावट आई। उस समय देश की अर्थव्यवस्था उछाल पर थी। क्या इसका यह मतलब है कि असम में एनआरसी शुरू होने से यह व्यवधान आया?

सरकार को यह तय कर लेना होगा कि विकास उसकी प्राथमिकता है या नहीं। अभी उच्च वृद्धि और पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था काफी मुश्किल लग रही है। लेकिन अगर यह अपने नागरिकता प्रस्तावों पर आगे बढ़ती है तो इससे केंद्र एवं राज्यों के बीच तनातनी, सामाजिक वैमनस्य और गरीबों की जिंदगी पर असर देखने को मिलेंगे। इस स्थिति में उसे विकास लक्ष्यों को तिलांजलि देनी होगी। सत्ताधारी दल को स्वीकार करना चाहिए कि गत 70 वर्षों में भारत एक धर्मनिरपेक्ष एवं उदार लोकतंत्र बना है और इसके आम नागरिकों के मन में यह संकल्पना गहराई तक पैठी हुई है। भारत को लेकर अंतरराष्ट्रीय जगत की छवि भी कुछ ऐसी ही है।

बैंकों के कर्ज समाधान पर नए नियमों का जोखिम भरा दांव

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

नए कानून में प्रस्तावित यह प्रावधान भी काफी परेशान करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समाधान एवं परिसमापन की कार्रवाई सरकार के साथ मशविरे के बाद की जाएगी।

गत 15 नवंबर को सरकार ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में बड़ा बदलाव लेकर आई। उसने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया नियम, 2019 की अधिसूचना जारी की जिसका मकसद बैंकों से इतर वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) के ऋणशोधन एवं परिसमापन का एक ढांचा मुहैया कराना है।

फिर यह स्पष्ट किया गया कि नए नियम एफएसपी या सरकार द्वारा आईबीसी की धारा 227 के तहत समय-समय पर अधिसूचित होने वाली एफएसपी श्रेणी पर ही लागू होंगे। याद रखें कि आईबीसी कानून वर्ष 2016 में कंपनी निकायों, सीमित जवाबदेही भागीदारी, साझेदारी फर्मों और लोगों के समयबद्ध ऋण पुनर्गठन, ऋण समाधान और परिसमापन के लिए समेकित मसौदे के तौर पर लाया गया था।

यह एक अंतरिम उपाय था। सरकार ने उस समय यह कहा था कि आईबीसी की धारा 227 के तहत वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए नियमों की यह अधिसूचना बैंकों एवं व्यवस्थागत रूप से अहम अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के वित्तीय समाधान की दिशा में समग्र कदम उठाए जाने के पहले एक अनिवार्य उपाय की अंतरिम व्यवस्था है।

इस तरह वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए की गई विशेष व्यवस्था के तीन अहम पहलू थे। पहला, इनमें बैंकों को शामिल नहीं किया गया था। दूसरा, किसी भी वित्तीय सेवा प्रदाता के लिए कर्ज समाधान एवं परिसमापन कार्रवाई शुरू करने के पहले मौजूदा नियामकों से सलाह एवं उनकी सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य किया गया था। तीसरा, बैंकों एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के दिवालिया समाधान एवं परिसमापन से जुड़े मामलों के लिए एक अलग कानून लाने की योजना थी।

यह कानूनी ढांचा आने के कुछ हफ्तों में ही सरकार अपने वादे वाले कानून पर अंदरूनी बातचीत शुरू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ती दिखी। इसके आईबीसी की धारा 227 के तहत बनाए गए कानूनों से अधिक विस्तारित होने की संभावना है। सरकार ने नए कानून की रूपरेखा अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। लेकिन एक ऑनलाइन वित्तीय प्रकाशन मनीलाइफ ने बैंकों एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के ऋणशोधन एवं परिसमापन पर नए कानून के प्रमुख बिंदुओं को सामने रखा है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) के थॉमस फ्रैंको ने भी ऑनलाइन वीडियो नेटवर्क न्यूजक्लिक पर एक कार्यक्रम में प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का जिक्र किया है।

ऐसा लगता है कि नए कानून को वित्तीय क्षेत्र विकास एवं नियमन (समाधान) विधेयक का नाम दिया जाएगा। इसी तरह का एक प्रस्ताव वर्ष 2017 में वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक (एफआरडीआई) के रूप में पेश किया गया था लेकिन इसके बेल-इन प्रावधानों का व्यापक विरोध होने पर सरकार ने वर्ष 2018 में अपने कदम पीछे खींचते हुए विधेयक को वापस ले लिया था। एफआरडीआई में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था कि वित्तीय संकट में फंसने पर बैंकों में नई पूंजी डालने के लिए जमाकर्ताओं की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि बीमित की जाने वाली जमा राशि की सीमा बढ़ाई जाएगी। लेकिन यह आश्वासन भी लोगों की चिंताओं को दूर नहीं कर सका और इस विधेयक को वापस ले लिया गया।

नए विधेयक में संभवत: जमाराशि के इस्तेमाल जैसा कोई भी बेल-इन प्रावधान नहीं रखा गया है लेकिन इसमें समाधान अधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक बैंक या वित्तीय कंपनी और ग्राहक के बीच के अनुबंध को निरस्त, संशोधित या परिवर्तित कर सकता है। समाधान अधिकरण ही अनुबंध में संशोधन या काट-छांट की सीमा तय करेगा। इस अधिकरण में वित्तीय क्षेत्र के मौजूदा नियामकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरे शब्दों में, बेल-इन प्रावधान की जगह वैसे ही समस्यापरक प्रावधान को रखा गया है क्योंकि इसमें समाधान अधिकरण को जमाकर्ताओं के साथ हुए अनुबंध में संशोधन का अधिकार होगा। हाल के समय में बैंक ग्राहकों की यह चिंता बढ़ी है कि बैंक के दिवालिया होने की सूरत में वे अपना जमा गंवा सकते हैं।

नए विधेयक में बीमा कवर लायक जमा राशि की सीमा बढ़ाए जाने की भी संभावना है। बीमा कवर के दायरे में लाई जाने वाली जमा राशि का निर्धारण समाधान अधिकरण करेगा। हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह गणना किस तरह की जाएगी? नए कानून में प्रस्तावित यह प्रावधान भी काफी परेशान करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समाधान एवं परिसमापन की कार्रवाई सरकार के साथ मशविरे के बाद की जाएगी।

पिछले दो महीनों की घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार नए कानून से जुड़े एक और बड़े विवाद के लिए खुद को तैयार कर रही है। क्या सरकार को बैंकों के लिए कर्ज समाधान पर इस तरह का कानूनी प्रस्ताव तैयार करने के पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? इसी मकसद से लाए गए पिछले विधेयक एफआरडीआई पर देश भर में विरोध हुआ था और सरकार को उसे वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। क्या सरकार को उस प्रकरण से वाजिब सबक नहीं सीखना चाहिए था?

कानाफूसी

एक और बसपा?

हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाली पूर्व लोकसभा सांसद सावित्री बाई फुले ने एक नई पार्टी का गठन किया है। पार्टी का नाम है कांशीराम बहुजन समाज पार्टी। उनका कहना है कि यह नई पार्टी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने संबंधी उनके देशव्यापी अभियान को जबरदस्त जन समर्थन मिला जिसके बाद उन्होंने नई पार्टी का गठन करने का निर्णय लिया। फुले सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थीं लेकिन 2019 के आम चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। वह उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय क्षेत्र से दोबारा चुनाव जीतने में नाकाम रहीं और भाजपा प्रत्याशी से हार गईं। बहरहाल, उनका कांग्रेस से भी मोहभंग हो गया क्योंकि उन्हें पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम में स्थान नहीं मिला।

कौन जिम्मेदार?

सोमवार को जब राजधानी नई दिल्ली के कई हिस्सों में जाम लगा तो लोगों ने इसका दोष दक्षिण-पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शन पर डाला। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार थीं। दरअसल जयप्रकाश नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के अवसर पर भाजपा मुख्यालय पर भारी भीड़ उमड़ी थी। इस आयोजन में निवर्तमान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। लगभग उसी समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए रोड शो का आयोजन किया था। हालांकि उनका नामांकन टल गया। केजरीवाल ने कहा कि शाम तीन बजे ही कार्यालय बंद होने के कारण वह नामांकन दाखिल नहीं कर सके। हालांकि कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए टिप्पणी की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ज्योतिषियों की सलाह पर अपना नामांकन टाला हो।

आपका पक्ष

बेरोजगारी के लिए सरकार ही दोषी नहीं

देश में बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार के प्रयास नाकाफी हैं और इसके लिए इनकी कुछ नीतियां भी जिम्मेदार हैं। लेकिन बेरोजगारी के लिए पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार नहीं हैं। सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए ऐसा नामुमकिन है। सरकारी नौकरियों का दायरा सीमित है और बेरोजगारी की समस्या विकराल है। हर कोई बाबू (अफसर) ही बन जाए यह संभव नहीं है। जो युवा या अन्य लोग बेरोजगारी के लिए केवल सरकार को दोष देते हैं उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या बेरोजगारी के लिए देश की बढ़ती जनसंख्या जिम्मेदार नहीं हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां कृषि में भी रोजगार के काफी अवसर हैं। देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन इस कृषि योग्य भूमि के मालिक के पुत्र पढ़-लिखकर कृषि करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और बाबू बनने की लालसा में बेरोजगार रह जाते हैं। कृषि करने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती हैं और किसानों को प्रोत्साहित भी करती हैं। देश में पर्यटन में भी रोजगार के काफी अवसर हैं। इसमें बेरोजगार युवा रोजगार क्यों नहीं तलाशते हैं। सरकार कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देती है और युवाओं को इसमें रोजगार शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। बेरोजगारों को नौकरी की तलाश के साथ स्वरोजगार या अन्य साधनों में भी रोजगार की तलाश करनी चाहिए।

रोजगार की तलाश के साथ युवाओं को स्वरोजगार अपनाने पर भी जोर देना चाहिए

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

जल संरक्षण के लिए प्रयास हों

जल संरक्षण के लिए हमें सदैव एक जिम्मेदार नागरिक की तरह प्रयास करते रहना चाहिए। सभी जीवों के लिए पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायु के बाद पानी दूसरा सबसे जरूरी पदार्थ है। जीवन की शुरुआत से ही पानी इतना महत्त्वपूर्ण है कि सभी प्रमुख सभ्यता नदी के पास ही विकसित हुई हैं। भारत में प्रमुख शहरों को विकसित करने में नदियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आज वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हवा में कुछ जमे हुए पानी के कण और नमी मिली थी। मानव की भूलों का ही परिणाम है कि आज धरती पर जल संकट होने लगा है। लगातार बढ़ता प्रदूषण और जल संचयन का अभाव इसके मुख्य कारण हैं। प्रकृति के साथ हमने बहुत खिलवाड़ कर लिया और इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हमारी धरती के जल स्रोत को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वह जल प्रदूषण है। नदियों में प्लास्टिक, कूड़ा-कचरा डालना, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में बहाने से वे प्रदूषित हो गई हैं। नदियों में कूड़ा डालने के कारण धारा प्रवाह कम होता चला गया है और नदियां सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। अगर इसी तरह हम नदी, तालाबों को प्रदूषित करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब नदियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। पृथ्वी पर जल एक असीम प्राकृतिक संसाधन है जो पुन: चक्रण द्वारा बनता है। लेकिन ताजा और पीने योग्य पानी हमारी प्रमुख आवश्यकता है जिसे हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बचाया जाना चाहिए। पानी को बचाने के प्रयास के बिना एक दिन पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। अत: जल संरक्षण के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

अनु मिश्रा, सीवान

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

18 फीसदी बढ़ सकते हैं पाम तेल के दाम

इंडोनेशिया और मलेशिया में बायोडीजल कार्यक्रम तथा कम आपूर्ति के कारण वर्ष 2020 में बढ़ेंगे दाम

रॉयटर्स
कुआलालम्पुर, 21 जनवरी

पाम तेल के औसत दामों में इस साल 17.9 प्रतिशत का इजाफा होगा। साल की पहली छमाही के दौरान उत्पादन में कमी तथा शीर्ष उत्पादकों – इंडोनेशिया और मलेशिया में बायोडीजल की अधिक खपत की वजह से बाजार में आपूर्ति में कमी होगी। रॉयटर्स द्वारा उद्योग के भागीदारों पर किए गए एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है। यह सर्वेक्षण 18 विश्लेषकों और उद्योग के भागीदारों पर किया गया है। सर्वेक्षण में जताए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में बेंचमार्क पाम तेल के औसत दाम 2,650 रिंगिट (650.80 डॉलर) प्रति टन रहेंगे, जबकि पिछले साल दाम 2,248 रिंगिट थे।

इंडोनेशिया पाम तेल बोर्ड के चेयरमैन डेरोम बंगुन ने कहा कि पहली तिमाही में तुलनात्मक रूप से कम उत्पादन के कारण यह केवल निर्यात के लिए ही पर्याप्त होगा। इससे स्टॉक में इजाफा नहीं होगा। मुंबई स्थित वनस्पति तेल आयातक सनविन ग्रुप के मुख्य कार्यकारी संदीप बाजोरिया ने कहा कि अलबत्ता इस साल बाद में आपूर्ति में मजबूती आने की उम्मीद है और अप्रैल से दिसंबर के बीच दाम काफी कम रह सकते हैं।

वर्ष 2020 में इंडोनेशिया का पाम उत्पादन 0.55 प्रतिशत बढ़कर 4.575 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2019 में उत्पादन अनुमानित रूप से 4.55 करोड़ टन रहा है। खास तौर पर इंडोनेशिया के पाम क्षेत्र से संबंधित सवालों के जवाब में सर्वेक्षण में शामिल 14 लोगों ने यह अनुमान जताया है। सूत्रों ने कहा कि वर्ष 2018 के कुल 4.3 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2019 में उत्पादन की वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही है।

वर्ष 2020 में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक मलेशिया में उत्पादन की वृद्धि दर में 0.35 प्रतिशत तक का इजाफा होगा और यह बढ़कर 1.993 करोड़ टन हो जाएगा। वर्ष 2019 में मलेशिया का उत्पादन 1.85 प्रतिशत बढ़कर 1.986 करोड़ टन हो गया, जबकि वर्ष 2018 में यह 1.95 करोड़ टन था। पिछले साल इन दोनों देशों में शुष्क मौसम और उर्वरक के कम उपयोग के कारण उत्पादन वृद्धि दर सुस्त रही है। तब पाम के दाम लुढ़ककर 1,960 रिंगित प्रति टन हो गए थे। वैश्विक पाम उत्पादन में इंडोनेशिया और मलेशिया का संयुक्त रूप से योगदान तकरीबन 90 प्रतिशत रहता है।

मलेशिया के क्वांटस कोर्प के महाप्रबंधक क्रिस्टोफर चई ने कहा कि वर्ष 2020 में काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इंडोनेशिया एक करोड़ किलोलीटर बायोडीजल का उत्पादन कर सकता है या नहीं। व्यापारियों ने कहा कि बाजार इंडोनेशिया के बी30 बायोडीजल कार्यक्रम (30 प्रतिशत पाम के साथ बायोडीजल) और मलेशिया के नए शुरू किए गए बी-20 कार्यक्रम पर बारीकी से नजर रखेगा, क्योंकि उम्मीद है कि ये दोनों देश मिलकर स्थानीय खपत में 10 से 13 प्रतिशत तक का इजाफा करेंगे।

इंडोनेशिया इस साल एक करोड़ किलोलीटर (87 लाख टन) बायोडीजल उत्पादन का लक्ष्य बना रहा है, जबकि मलेशिया के बायोडीजल संगठन को 17 लाख से 20 लाख टन ईंधन उत्पादन किए जाने की उम्मीद है।

सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने कहा कि चीन और अमेरिका, भारत और मलेशिया तथा यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया के बीच चल रहे व्यापार विवाद से इस साल निर्यात पर असर पड़ेगा। सिंगापुर स्थित पाम ऑयल एनालिटिक्स के सह-संस्थापक और मालिक सथिया वर्का ने कहा कि इंडोनेशिया के बायोडीजल निर्यातकों पर डंपिंगरोधी शुल्क लगाए जाने को लेकर इंडोनेशिया का यूरोपीय संघ के साथ विवाद मीडिया का ध्यान आकर्षित करेगा। वर्ष 2019 में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से मलेशिया को फायदा पहुंचा है। चीन को किए जाने वाले इसके निर्यात में पिछले साल 33.9 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि इन दोनों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच किसी व्यापारिक समझौते से चीन अमेरिका से दोबारा सोयाबीन की खरीद शुरू कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप पाम तेल की मांग में कमी आएगी।

सर्वेक्षण में खुलासा

- रॉयटर्स द्वारा उद्योग के भागीदारों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई
- सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में बेंचमार्क पाम तेल के औसत दाम 2,650 रिंगिट (650.80 डॉलर) प्रति टन रहेंगे, जबकि पिछले साल दाम 2,248 रिंगिट थे
- सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने कहा कि चीन और अमेरिका, भारत और मलेशिया तथा यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया के बीच व्यापार विवाद से इस साल निर्यात पर असर पड़ेगा

सरकार से आयातित धातु कबाड़ पर शुल्क कटौती की मांग

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 21 जनवरी

देश के अलौह धातु उत्पादन में तकरीबन आधा योगदान करने वाले द्वितीयक धातु उत्पादकों ने सरकार से आयातित कच्चे माल यानी धातुओं के कबाड़ पर सीमा शुल्क कम करने का अनुरोध किया है। इससे रोजगार परक घरेलू प्रसंस्करण उद्योग को कार्य क्षेत्र में समान स्तर मिलेगा और एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) वाले देशों से तैयार उत्पादों का सस्ता आयात कम होगा। देश के द्वितीयक अलौह धातु उत्पादकों को तांबे और एल्युमीनियम के आयातित धातु कबाड़ पर 2.5 प्रतिशत तथा जस्ते और सीसे पर पांच प्रतिशत वाली उलट सीमा शुल्क संरचना का सामना करना पड़ता है, जबकि एफटीए देशों से आयातित इन धातुओं के तैयार उत्पादों पर शून्य शुल्क लगता है। इसका मतलब यह है कि तैयार उत्पादों के मुकाबले कच्चे माल का आयात 2.5 से पांच प्रतिशत तक महंगा पड़ेगा। इससे प्रसंस्करण की लागत और बढ़ जाएगी तथा वैश्विक बाजार में देश के उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगी।

मैटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमआरएआई) के अध्यक्ष संजय मेहता ने कहा कि दुनिया भर में धातु कबाड़ के इस्तेमाल को पर्यावरण अनुकूल सामग्री के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, जबकि भारत सरकार धातु कबाड़ पर 2.5 से पांच प्रतिशत के दायरे में मूल सीमा शुल्क लगा रही है जिसे भविष्य की दृष्टि से पर्यावरण पर असर कम करने के लिए शून्य प्रतिशत करना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में समान स्तर उपलब्ध होगा और घरेलू द्वितीयक धातु उत्पादकों के लिए उलट शुल्क संरचना की समस्या हल होगी। मेहता ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री के लिए बजट से पहले सुझाव है कि धातु रीसाइक्लिंग को तरजीही क्षेत्र के तौर पर माना जाए।

किसी नई धातु की तुलना में कबाड़ प्रसंस्करण से सबसे बड़ा लाभ ऊर्जा बचत के रूप में मिलता है। लौह और इस्पात कबाड़ के लिए इसका दायरा 74 प्रतिशत, एल्युमीनियम कबाड़ के लिए 95 प्रतिशत, तांबे के कबाड़ के लिए 85 प्रतिशत, जस्ते के कबाड़ के लिए 76 प्रतिशत और सीसे के कबाड़ के लिए यह 65 प्रतिशत होता है। इसके अलावा कबाड़ रीसाइक्लिंग ने देश भर में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 80 लाख से एक करोड़ तक लोगों को रोजगार दिया हुआ है।

मेहता ने कहा कि देश की कुल कबाड़ खपत में 35 प्रतिशत धातु कबाड़ घरेलू संग्रह के जरिये उत्पन्न किया जा रहा है और बाकी 65 प्रतिशत आयात के जरिये मिलता है। लेकिन एल्युमीनियम कबाड़ की कुछ किस्में करीब 90 प्रतिशत तक आयातित स्रोतों पर निर्भर रहती हैं क्योंकि देश में इस किस्म का कबाड़ उत्पादन नहीं होता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि आयातित कबाड़ में अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री होती है जो उचित कबाड़ संग्रह की कमी के कारण देश में सीमित रहती है।

- द्वितीयक धातु उत्पादकों ने बजट से पहले वित्त मंत्री से किया अनुरोध
- धातु रीसाइक्लिंग को तरजीही क्षेत्र के तौर पर माने जाने का वित्त मंत्री को दिए गए सुझाव

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 21	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,807.0	4.1	2,064.3	8.0
Copper	6,245.0	7.3	6,544.0	8.8
Nickel	13,845.0	-14.5	14,674.9	-14.4
Lead	1,982.0	-10.0	2,204.7	4.6
Tin	17,775.0	5.6	18,466.5	3.5
Zinc	2,461.0	-1.6	2,626.0	-0.1
Gold ($/ounce)	1,557.2*	4.9	1,740.8	4.3
Silver ($/ounce)	18.0*	2.5	20.3	2.7
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	63.6*	8.7	65.1	9.3
Natural Gas ($/mmBtu)	1.9*	-13.8	1.9	-13.3
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	200.1	14.3	299.8	3.1
Maize	192.1*	4.2	278.3	-11.9
Sugar	399.4*	18.4	489.2	-0.1
Palm oil	765.0	43.0	1,223.5	41.5
Rubber	1,516.5*	10.6	1,937.9	14.0
Coffee Robusta	1,276.0*	5.5	1,776.4	-6.7
Cotton	1,556.2	9.3	1,619.9	0.6

* As on Jan 21, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.2& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	58.9	32988
Oil and Oilseeds	299.5	86008
Spices	1.3	9
Metal(Jan 20)		
Metal- non ferrous	5131.4	51453
Metal- precious	6382.7	407
Oil and gas(Jan 20)		
Gas	2737.8	64794
Oil	8346.9	1494

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	204.3	122314
Grains	85.1	98325
Oil and Oilseeds	592.8	480145
Others	57.0	66210
Pulses	54.7	27485
Spices	30.3	22526

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Aluminium (May 29)	142.7	1.2
Nickel (Jan 31)	1035.2	1.1
Aluminium Mini (Jan 31)	141.3	0.5
Crude Oil (Feb 19)	4182.0	0.5
Copper (Jan 31)	455.5	0.2
Gold Petal (Jan 31)	3974.0	0.0
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Jan 28)	137.8	-3.5
Cardamom (Feb 14)	3841.2	-2.8
Mentha Oil (Jan 31)	1235.5	-1.4
Kapas (Apr 30)	1112.5	-1.1
Crude Palm Oil (Jan 31)	795.6	-0.8
Zinc Mini (Jan 31)	182.6	-0.8

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Chana-Bikaner (Mar 20)	4164.0	0.6
Barley Jaipur (Apr 20)	1730.0	0.5
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	4142.0	0.3
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6264.0	0.3
Guar Seed 10 (Feb 20)	4106.0	0.1
Losers (* % Change)		
Wheat-Kota (Feb 20)	2135.0	-5.8
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	2013.0	-2.8
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1113.0	-1.2
Bajra (Feb 20)	1963.0	-1.0
Jeera Unjha (Mar 20)	14780.0	-0.9
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	888.0	-0.5
Soyabean Indore (Feb 20)	4218.0	-0.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	2.0
Zinc Mumbai (May 29)	189.8	1.5
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19610.0	1.3
Lead Mum (May 29)	154.8	0.9
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46721.0	0.6
Silver Ahm (Mar 05)	46701.0	0.6
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1235.5	-10.2
Alumini-Mumbai (Jan 31)	141.3	-2.6
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	182.6	-2.3
Aluminium Mum (May 29)	142.7	-1.7
Lead Min Mumbai (Jan 31)	151.0	-1.5
Gold Petal-Mumbai (Jan 31)	3974.0	-0.7

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3316.0	3.6
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6264.0	3.1
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	790.3	1.5
Maize-Sangli (Feb 20)	1982.0	1.3
Moong-Merta City (Feb 20)	7807.0	1.2
Coriander-Kota (Apr 20)	6932.0	1.2
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1730.0	-20.9
Jeera Unjha (Mar 20)	14780.0	-6.5
Soy Bean Indore (Feb 20)	4218.0	-3.3
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	7305.0	-0.5
Bajra-Delhi (Feb 20)	1963.0	-0.4

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	109.....(109)
Aluminium ingots /kg	147.....(147)
Brass sheet cutting /kg	333.....(329)
Brass utensil scraps/kg	313.....(313)
Copper heavy scrap /kg	434.....(435)
Copper utensil scraps/kg	405.....(406)
Copper wire bar /kg	466.....(468)
Lead ingots /kg	157.....(157)
Nickel Cathodes /kg	1045.....(1050)
Tin slabs /kg	1315.....(1320)
Zinc slabs /kg	187.....(189)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10292.....(10292)
DCH - 32 /Qtl	11529.....(11529)
Jaydhar /Qtl	9926.....(9926)
Shankar- 6 /Qtl	11304.....(11304)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	883.....(883)
Castor Comm /10kg	873.....(873)
Ricebran oil/10kg	820.....(820)
Groundnut oil /10kg	1140.....(1140)
Linseed oil /10kg	965.....(965)
Karanji /10kg	800.....(800)
Palm oil /10kg	855.....(850)
Sunflower exp ref /10kg	900.....(905)
Sunflower oil exp /10kg	880.....(880)
Soyabean ref / 10kg	895.....(895)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3382-3585.....(3412-3585)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	57.95.....(58.54)
Brent Crude (UK)	63.74.....(64.69)
Brent Crude (WTI)	58.54.....(58.54)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.93.....(2)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	323.22.....(334.79)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.....(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	39854.....(39951)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40014.....(40112)
Silver.999/ kg	46410.....(46640)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19473.80	19399.90
Alumini-Mumbai (M)	1 K	146.35	145.05
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1970.00	1970.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1957.50	1957.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2177.75	2186.25
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3900.00	3833.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4213.90	4204.30
Castor Seed-Kadi (N)	X	4175.00	4160.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4219.65	4228.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4474.05	4400.00
Chana-Akola (N)	X	4200.00	4300.00
Coriander-Gondal (N)	X	6644.00	6600.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6813.75	6772.50
Coriander-Kota (N)	1 Q	6891.65	6847.30
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2125.00	2086.50
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2098.30	2054.45
Cotton-Kadi (N)	1 B	19472.20	19337.75
CPO-Kandla (M)	10 K	807.60	794.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	785.45	778.95
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	790.00	800.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	902.15	906.15
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1544.00	1550.35
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3437.55	3451.50
Gold Ahm (M)	10 G	39947.00	39851.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32086.00	32009.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4010.00	4001.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7377.95	7338.90
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4043.65	4034.70
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4070.00	4025.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1138.85	1130.10
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	103.40	104.80
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16500.00	16000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	15883.35	15800.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	900.00	900.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1060.45	1050.30
Kapas-Rajkot (N)	X	1066.25	1058.00
Lead Mum (M)	1 K	154.70	153.30
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1966.65	1965.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2313.35	2309.50
Maize-Erode (N)	X	1995.85	1950.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2205.00	2180.00
Maize-Sangli (N)	X	1973.10	1956.55
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4937.50	4912.50
Moong-Merta City (N)	1 Q	7770.00	7711.10
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4488.50	4449.90
Nickel Mumbai (M)	1 K	1034.80	1036.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3300.00	3200.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3229.00	3270.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	341.00	339.40
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34284.60	34045.45
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	885.00	885.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	779.00	778.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1900.00	1936.10
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5195.50	5270.65
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	880.00	871.25
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	908.20	908.40
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	903.70	897.70
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	919.00	921.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13800.00	13800.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13800.00	13800.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46617.00	46425.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4359.00	4363.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4280.00	4242.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4413.70	4393.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4293.00	4293.00
Soymeal Indore (N)	1 T	34680.00	34700.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	911.70	910.40
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	32300.00	32000.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32200.00	31700.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	29500.00	28870.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3275.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3394.80	3419.05
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3293.15	3315.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3485.70	3466.65
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3320.00	3306.90
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3160.65	3172.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6152.50	6077.50
Wheat Delhi (N)	1 Q	2268.90	2207.50
Wheat Kota (N)	1 Q	2181.50	2180.85
Wheat New Indore (N)	1 Q	2250.00	2212.50
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2105.00	2095.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2250.00	2250.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5650.00	5700.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5900.00	5775.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	187.25	186.90

* as on Jan 20, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (मंगलवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19710, 19710, 19570, 19610	2636	500	16888
Feb 28	19970, 19970, 19860, 19890	2041	366	13474
Mar 31	20210, 20210, 20140, 20150	102	15	1777
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	2068, 2081, 2009, 2013	60790	3561	90830
Mar 20	2096, 2108, 2035, 2042	16790	1339	18400
Apr 20	2120, 2121, 2065, 2073	4800	397	8040
May 20	2132, 2132, 2096, 2096	170	16	620
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1125, 1125, 1110.5, 1112.5	604	94	828
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1125, 1126, 1110, 1113	1575	928	4424
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	1980, 1980, 1960, 1963	160	3	120
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1730, 1730, 1730, 1730	50	2	1640
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	4104, 4124, 4074, 4106	18910	2142	89095
Mar 20	4144, 4164, 4122, 4146	1665	228	6215
Apr 20	4180, 4206, 4180, 4184	30	6	55
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	4126, 4168, 4118, 4142	2630	326	25815
Mar 20	4132, 4170, 4122, 4146	900	126	8960
Apr 20	4160, 4184, 4136, 4156	330	56	3195
May 20	4170, 4170, 4170, 4170	5	1	5
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	799.3, 801.6, 787, 795.6	13640	1073	33390
Mar 20	885.4, 885.4, 862, 877.4	9435	1076	27215
Apr 20	872, 874.2, 860.4, 870.6	810	144	3350
May 20	869.6, 869.6, 864.8, 867.2	55	11	55
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4218, 4234, 4188, 4218	30675	3535	179505
Mar 20	4224, 4240, 4196, 4222	11675	1550	110770
Apr 20	4240, 4256, 4212, 4236	2885	482	36060
May 20	4244, 4256, 4236, 4252	1770	227	4350
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	7330, 7344, 7260, 7305	6250	989	54260
Mar 20	7405, 7440, 7360, 7400	1530	180	11950
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	4140, 4175, 4128, 4164	12180	941	22260
Apr 20	4125, 4157, 4120, 4145	910	81	4390
May 20	4140, 4160, 4140, 4160	60	6	780
Wheat-Kota NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	2135, 2135, 2135, 2135	10	1	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3885.1, 3940, 3825, 3841.2	1.7	17	6
Mar 13	3750, 3762.5, 3690.3, 3722.6	1.5	12	3.1
May 15	3862.5, 3862.5, 3862.5, 3862.5	0.1	1	0.1
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6940, 6975, 6870, 6932	720	68	9320
May 20	6935, 6970, 6935, 6970	30	3	310
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	14935, 14950, 14740, 14780	669	204	1929
Apr 20	14715, 14715, 14560, 14600	216	67	987
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6290, 6318, 6192, 6264	1300	248	5260
Apr 20	6190, 6196, 6102, 6172	595	117	4615
May 20	6250, 6250, 6170, 6232	30	6	105
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	141.05, 141.75, 140.65, 141.65	4370	2857	4416
Feb 28	142, 142.15, 141.4, 142.05	796	552	1811
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	454.25, 454.25, 450.2, 452.4	10910	3838	11900
Feb 28	454, 454, 450.25, 451	1940	605	4980
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	150.85, 151.45, 150.5, 151.35	5584	3377	5220
Feb 28	152.3, 152.3, 151.5, 152	1105	697	1833
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	1028, 1028, 1018, 1024.3	8796	5366	3562.5
Feb 28	1009, 1013.6, 1007.5, 1012.2	679.5	430	1059
Mar 31	1010, 1010, 1006.3, 1008.2	3	2	13.5
Zinc MCX(1 K)				
May 29	186.75, 186.75, 185.25, 185.95	8	8	4
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	182.05, 182.45, 181.25, 182.3	16123	9169	12956
Feb 28	183.5, 184.15, 182.65, 183.55	3622	2076	8670
Mar 31	184.85, 184.85, 184, 184.3	13	7	33

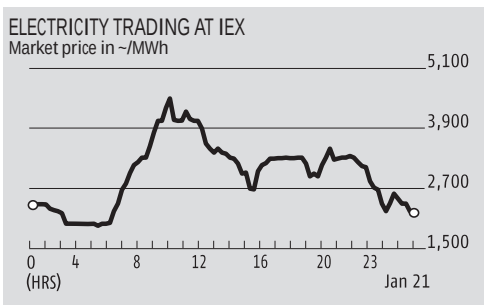

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	40090, 40176, 39820, 39853	7.51	6340	10.85
Apr 03	40100, 40290, 39937, 39976	0.94	736	12.02
Jun 05	40386, 40393, 40137, 40224	0.14	111	0.6
Gold Guinea MCX(8 G)				
Jan 31	31949, 31979, 31801, 31844	0	170	0
Feb 28	32175, 32175, 31810, 31839	0	164	0
Mar 31	31990, 31990, 31900, 31918	0	3	0
**Gold Mini MCX(10 G

व्यापार संबंधों में निष्पक्षता: गोयल

पीयूष गोयल बोले व्यापार संबंधों में समान शर्तों की है जरूरत और जलवायु परिवर्तन पर भारत है चिंतित

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत विभिन्न देशों के साथ व्यापार संबंधों में निष्पक्ष और समान शर्त हासिल करने को लेकर काम कर रहा है। विश्व आर्थिक मंच के सालाना सम्मेलन को मंगलवार को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में वृद्धि की अपार संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग का आह्वान किया।

गोयल ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौता भारत के लिए हस्ताक्षर करने के अनुकूल नहीं था। उन्होंने कहा, 'किसी भी समझौते में कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत खासतौर पर चीन और अन्य दूसरे देशों के साथ बड़े व्यापार घाटे से जूझ रहा है।' गोयल ने कहा कि आरसीईपी से भारत के हटने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि पहली बार भारत ने यह दिखाया कि व्यापार कूटनीतिक पहले से निर्देशित नहीं हो सकता।

हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआर) पर रणनीतिक परिदृश्य सत्र में उन्होंने यह भी कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है और निष्पक्ष आधार पर सहयोग पर जोर दे रहा है। गोयल ने कहा, 'निष्पक्ष और समान वितरण को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागर के आसपास के सभी देश महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पूरे सहयोग की भी उम्मीद करता है।' उन्होंने कहा, 'हम विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों में समान आधार पर शर्तों को रखने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।'

मंगलवार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका में आर्थिक तेजी का ऐसा दौर है जो इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं देखा गया था और अमेरिका के सपनों को पूरा करने का दौर वापस आ रहा है। उन्होंने जोरदार तरीके से यह कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए उग्र समाजवाद की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में ट्रंप ने कहा कि यह आशावाद का दौर है न कि निराशावाद का।

उन्होंने कहा, 'आज मैं इस बात की घोषणा करते हुए खुश हूं कि अमेरिका एक लाख करोड़ पौधे लगाने वाली पहल में शामिल होगा जिसकी शुरुआत विश्व आर्थिक मंच में हो रही है।' उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिहीनता के दौर के बाद अब अपार संभावनाओं का वक्त है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि अगर हम अपने लोगों की क्षमता का उपयोग करें, करों में कटौती करें, नियमन को सरल बनाएं, टूट चुके व्यापार समझौतों को पटरी पर लाएं और अमेरिकी ऊर्जा का पूर्ण उपयोग करें, तो समृद्धि जोरदार तरीके से लौट आएगी और वास्तव में यही हो रहा है।' उनके मुताबिक अमेरिका को चुनाव के बाद से ही 1.1 करोड़ नौकरियां मिली हैं और अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल के मुकाबले उनके कार्यकाल में औसत बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पर ही। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जैसी स्थिति बनने की बात पर उनका कहना था कि चीन के साथ अमेरिका का रिश्ता बेहतर है। उनका कहना है, 'हम मुश्किल दौर से गुजरे हैं लेकिन अब दोनों देशों के बीच सबकुछ सामान्य है।' ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत जल्द शुरू होगी।

भारत जिम्मेदार नहीं

गोयल ने कहा कि वैश्विक तापमान बढ़ाने में भारत की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है इसके बावजूद जीवाश्म ईंधन के मामले में भारत जवाबदेही के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाने वाले पश्चिमी देश पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। गोयल ने यह भी कहा कि भारत लोगों के साथ निवेशकों के हितों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और वे उनके लिए नियमन को और आसान बना रहा है। उन्होंने कहा, 'हम अपने लोगों को सही अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं और साथ ही निवेशकों के हितों की भी रक्षा करना चाहते हैं।'

कर व्यवस्था में बदलाव

भारत और कई अन्य देशों में वित्तीय असमानता की बढ़ती चुनौती के बीच एक अकादमिक जगत और अधिकार कार्यकर्ताओं से जुड़ी एक वैश्विक संस्था ने अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट कराधान व्यवस्था को टिकाऊ और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की।

इंटीपेंडेंट कमिशन फॉर दि रिफॉर्म ऑफ इंटरनैशनल कॉरपोरेट टैक्सेशन (आईसीआरआईसीटी) ने सोमवार को जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि असमानता के संकट पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है। इस वैश्विक संस्था का कहना है कि असमानता अनियंत्रित होती जा रही है और लाखों लोग बेहद अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 2,152 अरबपतियों के पास 4.6 अरब गरीब लोगों से ज्यादा संपत्ति है। संस्था ने कहा कि उसका मकसद अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट कर सुधार के विमर्श को आगे बढ़ाना है ताकि इसे सार्वजनिक हितों के नजरिये से देखा जा सके न कि किसी देश के फायदे के लिहाज से इस पर गौर किया जाए।

एआई खतरा नहीं

चीन की प्रमुख दूरसंचार कंपनी हुवावेई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक रेन झेंगफेई ने विश्व आर्थिक मंच की बैठक में कहा कि एक वक्त में परमाणु बल का खतरा सबसे ज्यादा था लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) को लेकर सबसे ज्यादा डर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि तकनीक का विकास अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा कि एआई के खतरे उतने स्पष्ट नहीं है और न ही यह परमाणु बम की तरह घातक है। उन्होंने कहा, 'आप इस दौड़ में जीत सकते हैं और दुनिया में अपना दबदबा बना सकते हैं। यह बातचीत पेइचिंग और सैनफ्रांसिस्को में होती है लेकिन वे यह नहीं समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है।'

अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी हुवावेई पर अमेरिकी कंपनियों के साथ काम करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके पीछे उसने हुवावेई से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का हवाला दिया है। हालांकि हुवावेई लगातार इससे इनकार करती रही है। झेंगफेई ने कहा, 'इस साल संभावना है कि अमेरिका हुवावेई के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ावा दे, लेकिन मेरा मानना है कि इससे हुवावेई का कारोबार बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा।' उन्होंने कहा कि कंपनी ने खुद को बचाने के लिए भारी मात्रा में निवेश किया है। इस साल हम पहले से तैयार हैं।

भारतीयों का विश्वास

दुनियाभर में लोग वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को लेकर मानव गतिविधियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जलवायु विज्ञान में उनके विश्वास का स्तर घट रहा है, लेकिन भारतीयों का विश्वास जलवायु विज्ञान पर सबसे ज्यादा है। यह बात मंगलवार को एक नए सर्वेक्षण में सामने आई। जलवायु विज्ञान में भरोसा और समकालिक घटनाओं से अवगत रहने के मामलों में भारतीय और बांग्लादेशी सबसे ऊपर हैं जबकि रूस और यूक्रेन इन दोनों ही मामलों में काफी पीछे हैं।

यह सर्वेक्षण विश्व आर्थिक मंच ने अपनी 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान प्रकाशित किया है। इसने साथ ही बेहतर जलवायु शिक्षा का आह्वान किया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि दुनियाभर में लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानव गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हैं और 2020 में कई क्षेत्रों में लोगों का जलवायु विज्ञान पर विश्वास कम हुआ है। *एजेंसियां*

लखनऊ में भाजपा की रैली को संबोधित करते गृहमंत्री अमित शाह (पीटीआई)

नागरिकता संशोधन कानून नहीं होगा वापस: अमित शाह

अर्चिस मोहन

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन पर सख्त रुख दिखाते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि केंद्र किसी भी परिस्थिति में नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं लेगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब बुधवार को उच्चतम न्यायालय इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सैकड़ों याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

इस कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा लखनऊ में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे वोट बैंक की राजनीति के लिए झूठ फैला रहे हैं। इस रैली में हिस्सा ले रहे लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा, 'विपक्ष हम पर चाहे कितना भी दबाव डाले लेकिन नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं लिया जाएगा।'

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सीएए, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) और राष्ट्रीय नगारिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर नौ 'झूठ' बोले हैं।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले तीन महीने में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य होगा शुरू

जब सिब्बल से एनपीआर पर उनकी पार्टी के रुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएए पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही एनपीआर और एनआरसी से संबंधित सभी मुद्दों का जवाब दिया जा सकता है। गौरतलब है कि एनपीआर की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसे एक अप्रैल से जनगणना के साथ शुरू किया जा रहा है। सिब्बल ने कहा कि अदालत का फैसला जो भी हो, लेकिन लोगों में सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर संदेह है और इसलिए वे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत के महा पंजीयक और जनगणना आयुक्त (आरजीआई) ने कई ट्वीट करते हुए कहा कि एकत्र किए जाने वाले ब्योरे सुरक्षित रहेंगे और अनुपालना न करने वालों पर जुर्माना लगेगा। आरजीआई ने कहा, 'आपके ब्योरों की गोपनीयता को लेकर जनगणना अधिनियम 1948 में गारंटी दी गई है। लेकिन इस कानून में अधिनियम के किसी भी प्रावधान का पालन न करने या उल्लंघन करने पर जनता और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।'

एक अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक जनगणना के हाउस लिस्टिंग फेज के साथ ही एनपीआर की मुहिम भी चलेगी। केरल और पश्चिम बंगाल सरकार कह चुकी हैं कि वे एनपीआर को लागू नहीं करेंगी। बहुत से गैर-भाजपा शासित राज्य सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे।

शाह ने लखनऊ में कहा कि संशोधित कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे किसी की नागरिकता छिनती है। शाह ने विपक्षी नेताओं- राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर उनके साथ बहस की चुनौती दी।

सिब्बल ने कहा कि वह मोदी और शाह को सीएए, एआरसी और एनपीआर पर बहस की चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह इस मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं कि यह कानून भेदभाव रहित है। सिब्बल बुधवार को उच्चतम न्यायालय में सीएए मामले में जिरह करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले नागरिकता से संबंधित किसी भी कानून और संशोधनों में धर्म के आधार पर भारत की नागरिकता देने का प्रावधान नहीं था। लेकिन मोदी सरकार द्वारा लाया गया कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है।

सिब्बल ने कहा कि सीएए और एनआरसी का आपस में कोई संबंध नहीं होने का दावा करना भी एक झूठ है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच संबंध होने का पता शाह के बयानों और पिछले साल संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति के संबोधन से चलता है। उन्होंने कहा कि ये बयान हाल के उन दावों की हवा निकालते हैं, जिनमें कहा गया है कि एनपीआर और एनआरसी के बीच कोई संबंध नहीं है। हालांकि यह साफ है कि एनपीआर एनआरसी का आधार बनेगा।

सिब्बल ने एनपीआर की अधिसूचना जारी नहीं होने के दावों को भी झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि एनपीआर की राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह एक अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि असम के अनुभव से यह झूठ उजागर हो गया है कि सीएए की प्रक्रिया से भारतीय नागरिक प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार और सशस्त्र बलों में सेवा दे चुके लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें 'संदेहास्पद' नागरिकों की सूची में डाल दिया गया।

सिब्बल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह दावा झूठ है कि उन्होंने ऐस 30,000 हिंदू प्रवासियों की पहचान की है, जिन्हें नागरिकता नहीं दी गई। उन्होंने कैसे इन प्रवासियों की पहचान की, जब सीएए के नियम नहीं बने हैं और न ही एनपीआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने कहा, 'सीएए, एनपीआर और एनआरसी में ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जिनसे इस देश का गरीब डर रहा है।'

शाह ने लखनऊ में कहा, 'अगर सीएए का कोई भी खंड मुस्लिमों समेत किसी की नागरिकता छीनता है तो वे मुझे बता सकते हैं। इस कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन गलत हैं।' उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनों के अनुपात में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तीन महीने में शुरू होगा।

आप को चुनौती भाजपा के लिए नहीं आसान

आप ने 2015 के चुनाव में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की

साई मनीष

चुनाव से कुछ महीने पहले 2019 में देश के कई छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम- किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत 2,000 रुपये डाले गए। इसके साथ यह वादा भी किया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में फिर से वापस आती है तब सभी श्रेणियों के किसानों को 4,000 रुपये और दिए जाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की 1,731 अवैध अवासीय कॉलोनी को अधिकृत किया जाएगा तब भाजपा को यही उम्मीद जगी कि जिस तरह लोकसभा चुनावों में पीएम-किसान का फायदा मिला ठीक उसी तरह पीएम-उदय (दिल्ली में प्रधानमंत्री अनाधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना) का फायदा दिल्ली के चुनावों में भी मिल सकता है।

निसंदेह पीएम-उदय योजना भाजपा की एकमात्र विश्वसनीय उपलब्धता होगी जिसके जरिये दिल्ली के नागरिकों को लुभाया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक 40 लाख लोगों को इस चुनाव पूर्व हुई घोषणा के लाभार्थी के तौर पर देखा जा रहा है और ये लोग दिल्ली के 1.46 करोड़ मतदाताओं का लगभग एक-तिहाई और 2 करोड़ आबादी का 20 फीसदी हिस्सा है।

कुछ दिन पहले ही भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा करने से पहले ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 20 लाभार्थियों को संपत्ति के दस्तावेज सौंपे।

भाजपा यह उम्मीद कर रही है कि 40 लाख में से बाकी मतदाता इस बात से प्रभावित हो सकते हैं कि 20 लोगों को संपत्ति के दस्तावेज मिल चुके हैं और वे पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बना सकते हैं। कॉलोनी के केवल इन्हीं लोगों के घर को वैध घोषित नहीं किया जा रहा है। सैनिक फार्म्स और छत्तरपुर सहित 67 अन्य पॉश कॉलोनी को इस बार छोड़ दिया गया है लेकिन यह वादा भी किया गया है कि अगले चरण के नियमीकरण के दौरान इन इलाकों को शामिल किया जाएगा। इन कॉलोनियों के दायरे को देखते हुए यह अंदाजा मिलता है कि भाजपा की इस पेशकश का असर 60-70 विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। करीब 10 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां कोई अवैध कॉलोनी नहीं है जिनमें मुस्लिम दबदबे वाला इलाका बल्लीमारन और मटिया महल शामिल है।

विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने जाते अरविंद केजरीवाल

पीएम-उदय योजना के अमल करने के तरीके और समय से यह अंदाजा मिलता है कि भाजपा को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। भाजपा के आत्मविश्वास की कमी की एक झलक इस फैसले में भी दिखती है कि पार्टी ने मोदी को दिल्ली में पार्टी का चेहरा बनाकर पेश किया है। वर्ष 2015 में पार्टी ने पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल किरन बेदी को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था जो पार्टी के लिए घातक साबित हुआ था। हालांकि 2013 में जब हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था तब पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। महत्त्वपूर्ण योजना का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखने और मोदी को दिल्ली में चेहरा बनाने की रणनीति से यह अंदाजा होता है कि पार्टी भी यह मान रही है कि मनोज तिवारी, विजय गोयल और हर्षवर्द्धन जैसे पार्टी के स्थानीय नेता भी दिल्ली में केजरीवाल के कद का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

मतदाताओं को लुभाने की कोशिश

1,731 अवैध कॉलोनियों को पीएम-उदय के तहत वैध बनाया गया है

40 लाख लोग या फिर एक-तिहाई मतदाता इन कॉलोनियों में रहते हैं

20 लाभार्थियों को संपत्ति के कागज दिए गए हैं

60 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी अवैध कॉलोनी है

इस दफा भाजपा ने जमीनी स्तर के चुनावी अभियान पर जोर दिया है। भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी चुनावी रैलियां आयोजित करने के बजाय बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हर घर में जाने और मोहल्ला बैठक करने का निर्देश दिया गया है। कई सालों से यही रणनीति केजरीवाल ने अपनाई है।

वर्ष 2013 और 2015 के चुनावों के दौरान आप कार्यकर्ता न केवल अवैध कॉलोनियों बल्कि घर-घर गए और इसके अलावा उन्होंने मध्यमवर्गीय आवासीय सोसायटी में भी दफ्तर के समय के बाद लोगों से मिलने और संपर्क साधने की रणनीति अपनाई ताकि स्थानीय उम्मीदवार के पक्ष में लोगों का मत जुटाया जा सके। आप को दिल्ली जैसे क्षेत्र के शहरी चुनाव में अपनी इस रणनीति का बेहद फायदा मिला जहां बड़ी चुनावी रैलियों की अपनी जटिलताएं हैं क्योंकि इसमें मतदाताओं के शामिल होने की अनिश्चितता के साथ-साथ भीड़ की उपस्थिति को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। पार्टी ने 2015 के चुनाव में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की जबकि 2013 में अपनी पहली चुनावी पारी के दौरान ही इसने 28 सीटें जीतकर कांग्रेस के साथ कुछ वक्त की सरकार बनाई थी। 2013 की चुनावी जीत की सफलता में निजी तौर पर संपर्क साधने और प्रचार के स्थानीय तरीकों को अपनाने की अहम भूमिका थी।

ऐसा लगता है कि भाजपा केजरीवाल को भ्रष्टाचार या फिर भाई-भतीजावाद के मोर्चे पर चुनौती देने के लिए भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। चुनाव के दौरान भाजपा के स्थानीय नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने कुप्रशासन या खराब प्रदर्शन जैसे आरोप रखे गए हैं लेकिन उनके सवालों का पर्याप्त जवाब उनके पास है।

ऐसे में मोदी, पीएम-उदय और शाह के आप से प्रेरित चुनावी अभियान की योजना का भाजपा के लिए क्या अर्थ है? 2015 के चुनावी अभियान के दौरान भी मोदी लहर के जादू को छोड़कर भाजपा के पास बताने लायक कोई उपलब्धि नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद पार्टी अब भी 32.19 फीसदी वोट हिस्सेदारी पाने में सफल है। हालांकि इसने 2015 के चुनावों में इसे 70 विधानसभा सीटों में से महज 3 सीटें मिली थीं। आप को न केवल ऐतिहासिक 67 सीटें मिलीं बल्कि कोई भी विपक्षी दल टक्कर नहीं दे पाया। वर्ष 2015 में आप के केवल चार उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन 5 फीसदी से कम था। इस बार भी भाजपा न केवल मोदी के चेहरे के साथ-साथ चुनाव से पहले की पेशकश करते हुए मतदाताओं को लुभाने की रणनीति बना रही है। लेकिन क्या भाजपा के ये कदम लोकप्रिय केजरीवाल को चुनौती देने के लिए काफी होंगे? 11 फरवरी को इस सवाल का जवाब मिल सकता है।